दैनिक
लद्दाख टुडे

Title Code: LDHIN00001 | वर्ष: 03 अंक: 208 | जम्मू, कश्मीर, लेह, मंगलवार 01 सितम्बर 2026 | पृष्ठ: 8 | मूल्य 2 रुपए

संक्षिप्त...

जेएंडके एसीबी ने एमडीएम 12.65 लाख रूपये के गबन के मामले में पूर्व जूनियर असिस्टेंट के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की

लद्दाख टूडे संवाददाता

जम्मू। जम्मू–कश्मीर एंटी–करप्शन ब्यूरो (एसीबी) ने सोमवार को ज़ोनल एजुकेशन ऑफिसर (ज़ेडईओ), मंजाकोट के ऑफिस में मिड–डे मील (एमडीएम) का काम देखने वाले तत्कालीन जूनियर असिस्टेंट मोहम्मद फारूक के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। यह मामला एमडीएम के चावल और खाना पकाने के खर्च में कथित हेराफेरी से जुड़ा है।

यह चार्जशीट एफआईआर नंबर 26/2018 के तहत दाखिल की गई, जो जेएंडके प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, 2006 की धारा 5(1)(सी), 5(1)(डी) और 5(2), तथा आरपीसी की धारा 465, 468, 471, 201 और 120–बी के तहत दर्ज की गई थी।

यह मामला 28 दिसंबर 2018 को पुलिस स्टेशन वीओजे (अब एसीबी–जे) में दर्ज किया गया था। जांच में मंजाकोट ज़ोन में 2014–15 की चौथी तिमाही के एमडीएम चावल में कथित हेराफेरी ■ शेष पेज 2...

मौसम विभाग: 1901 के बाद भारत में अगस्त सबसे गर्म रहा

नई दिल्ली। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने सोमवार को अपनी मासिक भविष्यवाणी में कहा कि सितंबर में पूरे भारत में मासिक बारिश सामान्य से कम होने की संभावना है। आईएमडी ने यह भी कहा कि 1901 के बाद से भारत में अगस्त 2026 सबसे गर्म रहा, जिसमें औसत तापमान 28.01 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

मौसम विभाग ने कहा कि सितंबर में बारिश के लॉन्ग पीरियड एवरेज (एलपीए) के 91 प्रतिशत से कम रहने की उम्मीद है।

एलपीए का मतलब है किसी खास इलाके में किसी तय समय (जैसे महीना या मौसम) में हुई बारिश का औसत, जिसे लंबे समय (आमतौर पर 30 से 50 साल) के आंकड़ों के आधार पर निकाला जाता है।

सितंबर के लिए, 1971 और 2020 के बीच के आंकड़ों के आधार पर एलपीए लगभग 167.9 मिमी है। आईएमडी ने यह भी कहा कि सितंबर के दौरान, मासिक औसत अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक ■ शेष पेज 2...

------ जम्मू ---------
अधिकतम – 29°C
न्यूनतम – 22°C
------- श्रीनगर -------
अधिकतम – 23°C
न्यूनतम – 19°C

पीएम मोदी ने बिश्केक में पुतिन, मसूद पेजेशकियन, निकोल पाशिनयान और सदिर झापारोव से मुलाकात कर पलटे सारे समीकरण

नई दिल्ली। बिश्केक में आयोजित हो रहे 26वें शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन के मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैश्विक कूटनीति के सबसे चर्चित और आकर्षक केंद्र के रूप में उभरे। यह भारत की बढ़ती वैश्विक हैसियत और मोदी की उस बहुपक्षीय कूटनीति का परिणाम है, जिसमें नई दिल्ली किसी एक खेमे की परछाई बनने की बजाय हर शक्ति केंद्र के साथ अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर संबंधों की नई इबारत लिख रही है। एससीओ के मंच से मोदी ने एक बार फिर संदेश दिया कि बदलती विश्व व्यवस्था में भारत अब समीकरण तय करने वाली ताकत बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है।

प्रधानमंत्री की द्विपक्षीय मुलाकातों पर चर्चा करें तो आपको बता दें कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ मोदी की द्विपक्षीय मुलाकात विशेष रूप से महत्वपूर्ण रही। यह बैठक ऐसे समय हुई, जब दुनिया की भू–राजनीति युद्ध, प्रतिबंधों, आर्थिक प्रतिस्पर्धा और नए शक्ति समीकरणों के दौर से गुजर रही है। ऐसे माहौल में भारत और रूस के शीर्ष नेतृत्व का संवाद

इस बात का स्पष्ट संकेत है कि दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी बाहरी दबावों से प्रभावित होने वाली नहीं है। मोदी की कूटनीतिक ताकत यही है कि वह एक तरफ रूस के साथ भारत के ऐतिहासिक और सामरिक संबंधों को मजबूती देते है, तो दूसरी तरफ पश्चिमी देशों, मध्य एशिया और पश्चिम एशिया के साथ भी भारत के हितों को समान दृढ़ता से आगे बढ़ाते है। यही संतुलन आज मोदी की विदेश नीति की सबसे बड़ी ताकत है। यानि संवाद सबसे करो, साझेदारी अपने हितों के आधार पर करो और फैसले पूरी तरह भारत की रणनीतिक प्राथमिकताओं के मुताबिक करो।

इसके अलावा, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन के साथ मोदी की मुलाकात सबसे अधिक सामरिक महत्व वाली बैठकों में शामिल रही। पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान के बीच नए सैन्य तनाव के बीच यह बैठक ऐसे समय हुई, जब पूरा क्षेत्र अस्थिरता के खतरनाक दौर से गुजर रहा है। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के साथ–साथ पश्चिम एशिया की तेजी से बदलती स्थिति पर विस्तार से चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने तनाव बढ़ने पर चिंता जताई और भारत का पुराना लेकिन बेहद स्पष्ट संदेश दोहराया कि विवादों का समाधान युद्ध से नहीं, संवाद और कूटनीति से होना चाहिए।

लेकिन भारत का रुख केवल शांति की अपील तक सीमित नहीं रहा। मोदी ने समुद्री नौवहन ■ शेष पेज 2...

एलजी मनोज सिन्हा ने इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी जेएंडके की सालाना आम बैठक की अध्यक्षता की

लद्दाख टूडे संवाददाता

श्रीनगर। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, जेएंडके यूटी की सालाना आम बैठक की अध्यक्षता की और इसके कामकाज, गतिविधियों और भविष्य की योजनाओं की समीक्षा की।

उपराज्यपाल, जो इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, जेएंडके यूटी के अध्यक्ष भी है, ने डिप्टी कमिश्नरों को निर्देश दिया कि वे रेड क्रॉस सोसाइटी की मानवीय और कल्याणकारी गतिविधियों को और मज़बूत करने

के लिए संसाधन जुटाने के काम में तेज़ी लाएं और फंड जुटाने के नए तरीके खोजें।

उन्होंने उन्हें प्राथमिकता वाले क्षेत्रों और ज़रूरी कामों की पहचान करके ज़िले–वार सालाना एक्टिविटी प्लान तैयार करने और उन्हें असरदार ढंग से लागू करने के लिए जमा करने का भी निर्देश दिया।

रेड क्रॉस की सेवाओं को लोगों तक और करीब ले जाने की ज़रूरत पर ज़ोर देते हुए, उपराज्यपाल ने दूर–दराज़ और सीमावर्ती इलाकों में अपनी पहुँच बढ़ाने का आह्वान किया।

उन्होंने डिप्टी कमिश्नरों को सलाह दी कि वे दूर–दराज़ के इलाकों में डायग्नोस्टिक सेंटर खोलने ■ शेष पेज 2...

रोज़ाना 400 रूपये : कम स्टाइपेंड के विरोध में मेडिकल इंटर्न हड़ताल पर, 30,000 रूपये करने की मांग

लद्दाख टूडे संवाददाता

जम्मू/श्रीनगर। जम्मू–कश्मीर के मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस और बीडीएस इंटर्न सोमवार को अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। वे सिर्फ 12,300 रुपये (यानी रोज़ाना लगभग 400 रुपये) के मासिक स्टाइपेंड का विरोध कर रहे है और इसे बढ़ाकर 30,000 रुपये करने की मांग कर रहे है।

विरोध कर रहे इंटर्न का कहना है कि कई बार अपील और विरोध–प्रदर्शन के बावजूद उनका स्टाइपेंड लगभग सात साल से नहीं बदला है, जबकि

दूसरे राज्यों में मेडिकल इंटर्न को इससे कहीं ज़्यादा पैसे मिलते है। प्रदर्शनकारियों द्वारा दिखाए गए तुलनात्मक आंकड़ों के अनुसार, ओडिशा 44,319 रुपये के मासिक स्टाइपेंड के साथ सूची में सबसे ऊपर है, जबकि पश्चिम बंगाल में मेडिकल इंटर्न को 43,099 रुपये और असम में 35,000 रुपये मिलते है।

प्रदर्शनकारी स्कीम्स बेमिना और जीएमसी श्रीनगर में मेडिकल कॉलेज अस्पतालों के बाहर लॉन में जमा हुए और जम्मू में कई जगहों पर धरना दिया। उन्होंने कहा कि सरकार से उनकी लंबे समय से लंबित मांग पर कोई प्रतिक्रिया न मिलने के बाद उन्हें काम बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ा। विरोध कर रहे एक इंटर्न ने कहा, "हमें काम छोड़ने और सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होना पड़ा है। हम बस इतना चाहते हैं कि हमारे काम के ■ शेष पेज 2...

रणनीतिक बदलाव का दौर; खतरों का स्वरूप बदल रहा है

नई चुनौतियां सामने आ रही हैं : एडमिरल स्वामीनाथन

मुंबई। पश्चिम एशिया में जारी संकट के बीच, नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन ने सोमवार को कहा कि यह रणनीतिक रूप से बड़े बदलाव का दौर है और समुद्री क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा लगातार बढ़ रही है।

उन्होंने कहा कि खतरों का स्वरूप लगातार बदल रहा है और नई–नई चुनौतियां व जटिलताएं सामने आ रही है। एडमिरल स्वामीनाथन मुंबई में भारतीय नौसेना में डीप–सी डाइविंग पोत आईएनएस

निपुण के शामिल किए जाने के मौके पर बोल रहे थे। इस जहाज में 300 मीटर की गहराई तक डाइविंग ऑपरेशन में मदद करने की क्षमता है। इसमें ■ शेष पेज 2...

गुलमर्ग में जेके के पहले इंटरनेशनल फ़िल्म फ़ेस्टिवल की तैयारियों की समीक्षा

लद्दाख टूडे संवाददाता

जम्मू। गुलमर्ग डेवलपमेंट अथारिटी के चीफ़ एग्जीक्यूटिव आफ़िसर तारिक हुसैन ने आज गुलमर्ग के कन्वेंशन सेंटर में जम्मू–कश्मीर के पहले इंटरनेशनल फ़िल्म फ़ेस्टिवल, 2026 की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की।

बैठक में गुलमर्ग में चल रही तैयारियों पर विस्तार से चर्चा की गई और यह सुनिश्चित करने पर ज़ोर दिया गया कि गुलमर्ग फ़िल्म निर्माताओं, क्रिएटिव प्रोफ़ेशनल्स और देश–विदेश से आने वाले पर्यटकों के सामने एक वर्ल्ड–क्लास डेस्टिनेशन के तौर पर पेश हो।

आने वाले डेलीगेट्स और मेहमानों के लिए एक दिन के कार्यक्रम के रोडमैप पर विस्तार से चर्चा की गई जिसमें गुलमर्ग की प्राकृतिक सुंदरता, एडवेंचर एक्टिविटीज़, मेहमाननवाज़ी, स्थानीय संस्कृति और पर्यटन के अन्य आकर्षणों को दिखाने पर ज़ोर दिया गया। प्रतिभागियों ने इस बात पर चर्चा की कि यह कार्यक्रम पर्यटकों को इस जगह का पूरा अनुभव ■ शेष पेज 2...

कर्नल सोफिया कुरैशी केस में सुप्रीम कोर्ट से बड़ा अपडेट

एसआईटी की जांच पूरी, क्या मप्र के मंत्री विजय शाह की बढ़ेगी मुश्किल?

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को कर्नल सोफिया कुरैशी पर मध्य प्रदेश के मंत्री कुंवर विजय शाह की विवादित टिप्पणी के मामले में सुनवाई हुई। इस दौरान शीर्ष अदालत को बताया गया कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद सेना की अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी को निशाना बनाकर टिप्पणी करने के मामले में मध्य प्रदेश के मंत्री कुंवर विजय शाह के खिलाफ अभियोजन के लिए मंजूरी का इंतजार है। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना

की पीठ को अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के. एम. नटराज ने बताया कि विशेष जांच दल (एसआईटी) की जांच पूरी हो चुकी है। सक्षम प्राधिकारी से मंजूरी मिलने के बाद आरोपपत्र दाखिल किया जाएगा।

पीठ ने अपने आदेश में कहा कि ■ शेष पेज 2...

लद्दाख में दलाई लामा ने नेपाल और तिब्बत में बाढ़ पीड़ितों के लिए प्रार्थना की

लद्दाख टूडे संवाददाता

लेह/जम्मू। तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा ने नेपाल के रसुवा इलाके और तिब्बत के कीरोंग में आई भयानक बाढ़ के पीड़ितों के लिए प्रार्थना की। इस बाढ़ में कई लोगों की जान गई और घरों व बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचा।

लेह में एक सभा को संबोधित करते हुए दलाई लामा ने कहा, "दोस्तों, आइए हम सब नेपाल और तिब्बत में इस भयानक

आपदा से पीड़ित सभी लोगों के लिए प्रार्थना करें चाहे वे मारे गए हों या बच गए हों। बाद में, उन्होंने रसुवा और कीरोंग में बाढ़ में मारे गए और अभी भी पीड़ित लोगों के लिए अवलोकितेश्वर के मंत्र ओम मणि पद्मे हुम का जाप करने में लोगों का नेतृत्व किया।

वे रविवार को चोगलमसर के पास शेवात्सेल टीचिंग ग्राउंड में लद्दाख बौद्ध संघ (एलबीए), ऑल लद्दाख गोम्पा एसोसिएशन (एएलजीए) और लद्दाख के तिब्बती समुदाय द्वारा आयोजित दीर्घायु प्रार्थना समारोह में बोल रहे थे। इस समारोह में लगभग 25,000 लोग शामिल हुए। उन्होंने तिब्बत और मुख्य भूमि चीन में बौद्ध धर्म के बने रहने और फलने–फूलने के लिए भी प्रार्थना ■ शेष पेज 2...

कश्मीर के मंडलायुक्त ने फल उत्पादकों से सस्ते ट्रांसपोर्टेशन के लिए रेलवे फ्रेट सर्विस का इस्तेमाल करने को कहा

फल ले जाने वाले ट्रक ड्राइवरों को नेशनल हाईवे पर तय लोड लिमिट का सख्ती से पालन करने की सलाह दी

लद्दाख टूडे संवाददाता

जम्मू/श्रीनगर। बागवानी उत्पादों, खासकर सेबों को देश की अलग–अलग मंडियों और विदेशों तक सस्ते और बिना किसी परेशानी के ट्रांसपोर्ट करने के मकसद से, कश्मीर के डिविजनल कमिश्नर अंशुल गर्ग ने आज फल उत्पादकों, व्यापारियों और दूसरे स्टेकहोल्डर्स से रेलवे की माल ढुलाई और फ्रेट सर्विस का ज्यादा इस्तेमाल करने की

अपील की।

डिविजनल कमिश्नर उस मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे थे जो कश्मीर से बागवानी उत्पादों के ट्रांसपोर्टेशन के लिए रेलवे फ्रेट सर्विस के इस्तेमाल की समीक्षा के लिए बुलाई गई थी।

मीटिंग के दौरान डिविजनल कमिश्नर ने सभी डिप्टी कमिश्नर और डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर प्लानिंग एंड मार्केटिंग को निर्देश दिया कि वे फल उत्पादकों, व्यापारियों, एसोसिएशन और एग्रीगेटर्स के साथ ■ शेष पेज 2...

जेएंडके कांग्रेस ने सीएम से मेडिकल इंटर्न का स्टाइपेंड बढ़ाने के लिए दखल देने को कहा

लद्दाख टूडे संवाददाता

जम्मू। जम्मू–कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा ने सोमवार को मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से अपील की कि वे मेडिकल इंटर्न के चल रहे विरोध–प्रदर्शन में दखल दें और उनके स्टाइपेंड में जल्द और सार्थक बढ़ोतरी सुनिश्चित करें।

विरोध कर रहे मेडिकल इंटर्न द्वारा जारी एक तुलनात्मक चार्ट के अनुसार, जम्मू–कश्मीर शायद एमबीबीएस और

बीडीएस इंटर्न को सबसे कम स्टाइपेंड (सिर्फ़ 12,300 रुपये महीना) देने वाला क्षेत्र बन गया है। इसी वजह से उन्होंने सोमवार को अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी और स्टाइपेंड को तुरंत बढ़ाकर 30,000 रुपये करने की मांग की।

मुख्यमंत्री को लिखे एक पत्र में कर्रा ने कहा कि विरोध कर रहे मेडिकल इंटर्न की मांग जायज़ है और उस पर "सहानुभूतिपूर्वक और तुरंत विचार" किया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि मेडिकल इंटर्न स्वास्थ्य सेवा प्रणाली का एक ■ शेष पेज 2...

सुरक्षा बलों ने शोपियां में आतंकियों के ठिकाने का भंडाफोड़ किया; हथियार और गोला–बारूद बरामद

लद्दाख टूडे संवाददाता

श्रीनगर। सोमवार को संयुक्त सुरक्षा बलों ने जम्मू–कश्मीर के शोपियां ज़िले में आतंकियों के एक ठिकाने का भंडाफोड़ किया और ऑपरेशन के दौरान हथियार व गोला–बारूद बरामद किए।

अधिकारियों ने बताया कि यह संयुक्त ऑपरेशन जेएंडके पुलिस, सेना की 44 राष्ट्रीय राइफल्स और सीआरपीएफ ने ज़िले के नाइकपोरा मेमेंडर इलाके में खास जानकारी मिलने पर चलाया था। अधिकारियों ने कहा, एक बाग वाले इलाके में तलाशी के दौरान, टीम ने एक ठिकाने का पता लगाया और हथियार व

गोला–बारूद बरामद किए, जिनमें एक एके–47 राइफल, दो एके–47 मैगज़ीन, 7.62 एमएम ■ शेष पेज 2...

Created by Universal Document Converter

शेष पेज 1 से

पीएम मोदी ने बिश्केक ...

और वाणिज्य की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने की जरूरत पर विशेष जोर दिया। उन्होंने साफ कहा कि नागरिकों, नागरिक प्रतिष्ठानों, वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों को किसी भी परिस्थिति में निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। यह बयान सामरिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है। फारस की खाड़ी और उसके आसपास बढ़ती अस्थिरता सीधे भारत की ऊर्जा सुरक्षा, समुद्री व्यापार और हिंद महासागर क्षेत्र के हितों को प्रभावित कर सकती है। भारत ने ईरान के साथ ब्रिक्स और एससीओ जैसे बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता भी दोहराई। मोदी ने राष्ट्रपति पेजेशकियन को भारत में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया। साफ है कि नई दिल्ली तेहरान से संवाद का दरवाजा खुला रखकर पश्चिम एशिया में अपने रणनी. तिक हितों की सुरक्षा कर रही है।

इसके अलावा, प्रधानमंत्री मोदी ने आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशिनयान से भी अलग द्विपक्षीय मुलाकात की। यह बैठक केवल औपचारिक कूटनीतिक बातचीत नहीं थी, बल्कि दक्षिण काकेशस में भारत की बढ़ती रणनीतिक मौजूदगी का संकेत भी थी। दोनों नेताओं ने रक्षा, आर्थिक सहयोग, फार्मास्यूटिकल्स, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, संस्कृति और शिक्षा समेत कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा की। क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों, विशेष रूप से पश्चिम एशिया की स्थिति पर भी विचारों का आदान–प्रदान हुआ। रक्षा सहयोग पर विशेष जोर बेहद महत्वपूर्ण है। आर्मेनिया के साथ बढ़ती साझेदारी भारत को काकेशस क्षेत्र में अपनी रणनीतिक पहुंच मजबूत करने का अवसर देती है। यह क्षेत्र यूरोप, रूस, पश्चिम एशिया और मध्य एशिया के बीच एक महत्वपूर्ण भू–राजनीतिक गलियारा है।

मोदी ने पाशिनयान को आश्वस्त किया कि भारत आर्मेनिया के साथ संबंधों को और गहरा करने के लिए तैयार है। दोनों देशों के बीच विश्वास का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी रहा कि हालिया पश्चिम एशियाई घटनाक्रम के दौरान ईरान में फंसे भारतीय नागरिकों की निकासी में आर्मेनिया ने सहयोग किया था। इससे स्पष्ट है कि भारत–आर्मेनिया संबंध अब केवल कागजी समझौतों तक सीमित नहीं हैं।

इसके अलावा, एससीओ सम्मेलन के मेजबान देश किर्गिज़ गणराज्य के राष्ट्रपति सदिर झापारोव के साथ मोदी की मुलाकात ने भारत–मध्य एशिया संबंधों को नई मजबूती दी। प्रधानमंत्री ने किर्गिज़स्तान के स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी और उसी दिन एससीओ सम्मेलन के उद्घाटन को विशेष महत्व वाला अवसर बताया। उन्होंने झापारोव को 26वें एससीओ शिखर सम्मेलन के सफल आयोजन के लिए भी बधाई दी। दोनों नेताओं ने भारत और किर्गिज़ गणराज्य के बीच रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा की और इसे और मजबूत करने की प्रतिबद्धता जताई। आर्थिक और वाणिज्यिक सहयोग बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया। दोनों अर्थव्यवस्थाओं की परस्पर पूरक क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए नए अवसर तलाशने पर सहमति बनी। छात्र आदान–प्रदान, सांस्कृतिक सहयोग और लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने पर भी चर्चा हुई। मोदी ने किर्गिज़ अध्यक्षता में आयोजित एससीओ बैठकों में भारत की मजबूत भागीदारी का उल्लेख करते हुए कहा कि यह दोनों देशों के बीच मौजूद आपसी सम्मान, विश्वास और सहयोग का प्रमाण है।

हम आपको यह भी बता दें कि बिश्केक पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने विभिन्न किर्गिज़ समुदायों के लोगों से भी मुलाकात की। सांस्कृतिक और योग गतिविधियों से जुड़े लोगों के साथ संवाद करते हुए उन्होंने भारत और किर्गिज़स्तान की पुरानी मित्रता को रेखांकित किया। इससे पहले, प्रधानमंत्री का स्वागत पारंपरिक किर्गिज़ नृत्य के साथ किया गया। यह सांस्कृतिक कूटनीति का वह पक्ष है जिसे भारत लगातार अपनी विदेश नीति के हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। सरकारों के बीच समझौते महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन दीर्घकालिक साझेदारी के लिए जनता के बीच विश्वास और सांस्कृतिक जुड़ाव उससे भी ज्यादा जरूरी है।

बहरहाल, बिश्केक में मोदी की इन द्विपक्षीय मुलाकातों का बड़ा संदेश साफ है कि भारत एक साथ कई मोर्चों पर खेल रहा है। रूस के साथ द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न आयामों को और विस्तार देने की बात हो, ईरान के साथ पश्चिम एशिया की सुरक्षा मुद्दे पर चर्चा हो, आर्मेनिया के साथ दक्षिण काकेशस में रणनीतिक सहयोग बढ़ाना हो और किर्गिज़स्तान के साथ मध्य एशिया में साझेदारी को नई ऊँचाई देनी हो, नई दिल्ली ने एससीओ के मंच को केवल सम्मेलन तक सीमित नहीं रहने दिया बल्कि अपने राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाने में भी इस अवसर का उपयोग किया। कुल मिलाकर, भारत ने बिश्केक में अपने हितों की ऐसी कूटनीतिक बिसात बिछाई, जिसका असर पश्चिम एशिया से लेकर मध्य एशिया और दक्षिण काकेशस तक दिखाई देगा।

एलजी मनोज सिन्हा न ...

की संभावनाओं पर विचार करें, खासकर उन जगहों पर जहाँ लोगों को अस्पतालों तक पहुँचने और ज़रूरी स्वास्थ्य सेवाएँ पाने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है।

उपराज्यपाल ने टीबी को पूरी तरह खत्म करने की दिशा में समन्वित प्रयासों को तेज़ करने और ज़मीनी स्तर पर टीबी मरीज़ों की सही पहचान, जाँच, इलाज और फ़ॉलो–अप सुनिश्चित करने का आह्वान किया।

उपराज्यपाल ने ज़ोर दिया कि रेड क्रॉस सोसाइटी को अपनी मानवीय भूमिका को और मज़बूत करना चाहिए और अपनी गतिविधियों का विस्तार करना चाहिए ताकि पूरे जम्मू–कश्मीर में समाज के कमज़ोर और ज़रूरतमंद वर्गों तक समय पर मदद और ज़रूरी सेवाएँ पहुँच सकें। उन्होंने आईआरसीएस जेएंडके के अधिकारियों को नशा–विरोधी अभियान को और तेज़ करने और श्नशा–मुक्त जम्मू–कश्मीरश बनाने में अपना बहुमूल्य योगदान देने का काम भी सौंपा।

आईआरसीएस जेएंडके के महासचिव शुभंकर प्रत्युष पाठक ने समीक्षा और मंजूरी के लिए एजेंडा के कई बिंदु पेश किए।

बैठक में बजट अनुमान, ऑडिट, ब्लड बैंक और डायग्नोस्टिक सेंटर में मेडिकल अधिकारियों की नियुक्ति और रेड क्रॉस सोसाइटी व उसकी ज़िला–स्तरीय इकाइयों द्वारा की जा रही गतिविधियों सहित कई महत्वपूर्ण मामलों पर भी चर्चा की गई।

डिप्टी कमिश्नरों ने उपराज्यपाल को अपने–अपने ज़िलों में की जा रही गतिविधियों के बारे में जानकारी दी और रेड क्रॉस सोसाइटी के कामकाज और पहुँच को और मज़बूत करने के लिए सुझाव दिए।

बैठक में उपराज्यपाल के प्रधान सचिव डॉ. मनदीप के. भंडारी शामिल हुए; शुभंकर प्रत्युष पाठक, जनरल सेक्रेटरी, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, जेएंडके; डिप्टी कमिश्नर (ज़िला रेड क्रॉस यूनिट के प्रेसिडेंट) और आईआरसीएस जेएंडके के अधिकारी।

रोज़ाना 400 रूपये : कम ...

घंटों के हिसाब से हमें स्टाइपेंड मिले।

एक इंटर्न डॉ. शाहनवाज़ ने कहा कि इस मांग को लेकर पूरे जेएंडके में एमबीबीएस और बीडीएस इंटर्न हड़ताल में शामिल हुए हैं। उन्होंने कहा, सात साल से हमारा स्टाइपेंड लगभग 12,300 रुपये ही है। कई दूसरे राज्यों में इंटर्न को 25,000 से 45,000 रुपये के बीच स्टाइपेंड मिल रहा है। हम भी वही काम करते हैं, जिसमें 24 घंटे और रात की शिफ्ट और ग्रामीण इलाकों में पोस्टिंग शामिल है, लेकिन हमें रोज़ाना सिर्फ़ 400 रुपये के आसपास ही मिलते हैं। उन्होंने बताया कि जेएंडके में इंटर्न को महीने में 12,300 रुपये मिलते हैं, जबकि कई राज्यों में स्टाइपेंड 30,000 से 45,000 रुपये या उससे ज़्यादा है।

उन्होंने कहा, हम मांग कर रहे हैं कि हमारा स्टाइपेंड बढ़ाकर 30,000 रुपये किया जाए। इंटर्न का कहना है कि मौजूदा स्टाइपेंड महंगाई और सरकारी मेडिकल कॉलेजों में उनके काम के बोझ के हिसाब से बहुत कम है। डॉ. शाहनवाज़ ने बताया कि इंटर्न ही सबसे पहले इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आने वाले मरीज़ों को देखते हैं और ओपीडी, वार्ड, प्रोसीजर और अस्पताल की दूसरी सेवाओं में डॉक्टरों की मदद भी करते हैं।

एक और इंटर्न ने कहा, लगातार ड्यूटी करने और काम का भारी बोझ उठाने के बावजूद, हमें महीने में सिर्फ़ 12,300 रुपये मिलते हैं। यह नाइंसाफ़ी है। एक और प्रदर्शनकारी, डॉ. अभिनव भट ने बताया कि 2023 में हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट की बनाई एक कमेटी ने 2025–26 के लिए स्टाइपेंड बढ़ाकर लगभग 25,000 रुपये करने की सिफ़ारिश की थी।

उन्होंने कहा, इसके बाद, 2026 के विधानसभा सत्र में यह मुद्दा उठाया गया और प्रस्तावित स्टाइपेंड लगभग 26,300 रुपये बताया गया। लेकिन इसके बावजूद, फ़ाइल अभी भी अटकी हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि इंटर्न को फ़ाइल की स्थिति के बारे में कोई साफ़ जवाब नहीं मिल पा रहा है और अधिकारी उन्हें अलग–अलग विभागों में भेज रहे हैं।

उन्होंने कहा, कभी–कभी हमें बताया जाता है कि फ़ाइल मुख्यमंत्री के पास भेज दी गई है, तो कभी कहा जाता है कि यह फ़ाइनेंस डिपार्टमेंट के पास है। हमें एक ऑफ़िस से दूसरे ऑफ़िस दौड़ाया जा रहा है। लिखित आश्वासन की मांग करते हुए उन्होंने कहा, हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती, तब तक हड़ताल जारी रहेगी। हमें लिखित आदेश चाहिए, सिर्फ़ आश्वासन नहीं। कश्मीर में प्रदर्शनकारियों ने कहा कि उन्होंने सरकार, जिसमें हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर सकीना इट्टू भी शामिल हैं, के सामने अपनी बात रखी थी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला।

एक महिला प्रदर्शनकारी ने कहा, ष्ये सफ़ेद एप्रन विरा. ेध–प्रदर्शन करने के लिए नहीं हैं, लेकिन जब कोई हमारी बात नहीं सुन रहा है तो हम क्या करें? हमें रोज़ाना 400 रुपये मिलते हैं, जो दिहाड़ी पर काम करने वाले अकुशल मज़दूर की कमाई से भी कम है। इंटर्न द्वारा दिखाए गए तुलनात्मक आंकड़ों के अनुसार, कर्नाटक में महीने का स्टाइपेंड 30,000 रुपये है, जबकि केरल में 27,300 रुपये और दिल्ली व मेघालय में 26,300 रुपये है। तेलंगाना में स्टाइपेंड 25,900 रूपये है, जबकि अरुणाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में यह 25,000 रूपये है। तमिलनाडु में स्टाइपेंड लगभग 25,000 रूपये है, इसके बाद हरियाणा में 24,310 रूपये और आंध्र प्रदेश में लगभग 21,840 रूपये है।

गुजरात, बिहार, गोवा और हिमाचल प्रदेश में यह राशि लगभग 20,000 रूपये प्रति माह है, जबकि पुडुचेरी में यह 18,000 रूपये है। इस चार्ट के मुताबिक, इन आंकड़ों की तुलना में जेएंडके में इंटर्न को हर महीने सिर्फ़ 12,300 रुपये मिलते हैं, जिससे यह केंद्र शासित प्रदेश इस तुलना में सबसे नीचे है।

कर्नल सोफिया कुरैशी ...

श्एसआईटी की रिपोर्ट में कहा गया है कि जांच पूरी हो चुकी है और रिपोर्ट को सीलबंद लिफाफे में रखा गया है। हालांकि, अभियोजन मंजूरी का मुद्दा अभी सक्षम प्राधिकारी के समक्ष विचाराधीन है। यह बताया गया है कि जैसे ही मंजूरी मिलती है, सक्षम अधिकार क्षेत्र वाली अदालत के समक्ष आरोपपत्र दाखिल कर दिया जाएगा। इसलिए, मंजूरी का मुद्दा अभी विचाराधीन है।श शीर्ष अदालत ने इन दलीलों का संज्ञान लेते हुए मामले की सुनवाई स्थगित कर दी।

कुंवर विजय शाह की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह ने कहा कि मंत्री ने अगले ही दिन सार्वजनिक रूप से माफी मांग ली थी और अदालत से अनुरोध किया कि उनकी माफी पर विचार किया जाए। पीठ ने कहा कि जांच रिपोर्ट अंततः सक्षम प्राधिकारी के पास जानी है। 28 जुलाई, 2025 को शीर्ष अदालत ने कर्नल कुरैशी के खिलाफ की गई टिप्पणी को लेकर सार्वजनिक माफी दर्ज नहीं कराने पर शाह को फटकार लगाई थी और कहा था कि वह अदालत के धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं।

अदालत ने कहा था कि मंत्री के आचरण से उसके इरादों और नेक नीयत को लेकर संदेह पैदा हो रहा है। इससे पहले शाह के वकील ने दलील दी थी कि मंत्री ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी थी, जिसे ऑनलाइन साझा किया गया था और अदालत के रिकॉर्ड में भी रखा जाएगा। 28 मई, 2025 को शीर्ष अदालत ने कर्नल कुरैशी के खिलाफ विवादित टिप्पणी को लेकर शाह के विरुद्ध मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में जारी कार्यवाही बंद करने का आद. ेश दिया था और एसआईटी से स्थिति रिपोर्ट मांगी थी।

इससे पहले शीर्ष अदालत ने कुंवर विजय शाह को फटकार लगाते हुए उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया था। शाह उस समय विवादों में घिर गए थे, जब एक वीडियो सामने आया था जिसमें उन्हें कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते देखा गया था। कर्नल कुरैशी ऑपरेशन सिंदूर पर मीडिया ब्रीफिंग के दौरान विंग कमांडर व्योमिका सिंह के साथ प्रमुखता से सामने आई थीं।

हाईकोर्ट ने कुंवर विजय शाह की टिप्पणियों को श्अपमान. जनकश बताते हुए उन्हें फटकार लगाई थी और कहा था कि उन्होंने कर्नल कुरैशी के खिलाफ श्घटिया भाषाश का इस्तेमाल किया। अदालत ने पुलिस को उनके खिलाफ वैमनस्य और घृणा फैलाने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया था। कड़ी आलोचना के बाद शाह ने खेद जताया था और कहा था कि वह कर्नल कुरैशी का अपनी बहन से भी अधिक सम्मान करते हैं। भारत ने अप्रैल 2025 में पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेने के लिए मई 2025 में पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) में नौ आतंकी ठिकानों को ऑपरेशन सिंदूर के तहत निशाना बनाया था, जिसमें 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए थे।

गुलमर्ग में जेके क ...

कैसे दे सकता है।

बैठक का मुख्य फ़ोकस नरबल से गुलमर्ग तक के पूरे रास्ते की ब्रांडिंग और सुंदरता बढ़ाने पर था जिसमें गुलमर्ग बाउल के अंदर प्रमुख जगहों और महत्वपूर्ण स्थानों को शामिल किया गया। प्रतिभागियों को निर्देश दिया गया कि वे यह सुनिश्चित करें कि रास्ता और मुख्य सार्वजनिक जगहें फ़ेस्टिवल की भावना को सही ढंग से दिखाएं और साथ ही जम्मू–कश्मीर की प्राकृतिक सुंदरता, पर्यटन इंफ़्रास्ट्रक्चर और सांस्कृतिक समृद्धि को भी प्रदर्शित करें।

बैठक में साफ़–सफ़ाई, हेल्थकेयर और इमरजेंसी हेल्थ सुविधाओं से जुड़ी व्यवस्थाओं की भी समीक्षा की गई जिसमें गणमान्य व्यक्तियों की यात्रा के दौरान उच्च मानक बनाए रखने पर ज़ोर दिया गया। संबंधित एजेंसियों से कहा गया कि वे महत्वपूर्ण स्थानों पर पर्याप्त मैनपावर, सुविधाएं और तुरंत प्रतिक्रिया देने वाले सिस्टम सुनिश्चित करें।

जीडीए के सीईओ ने प्रशासन, पुलिस, पर्यटन से जुड़े लोगों, स्वास्थ्य अधिकारियों, म्युनिसिपल निकायों, होटल इंडस्ट्री, केबल कार आपरेटरों और अन्य सर्विस प्रोवाइडर्स के बीच बेहतर तालमेल की अपील की ताकि इवेंट से पहले ही सभी व्यवस्थाएं पूरी हो जाएं।

रणनीतिक बदलाव का ...

पनडुब्बी से जुड़े बचाव कार्यों को तेजी से करने की भी क्षमता है। इसे आपदा राहत और मानवीय कार्यों के लिए भी तैनात किया जा सकता है।

एडमिरल स्वामीनाथन ने कहा, ष्हम आज रणनीतिक रूप से बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहे हैं; समुद्री क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा लगातार बढ़ रही है।

जेएंडके एसीबी न ...

का पता चला था। एसीबी के अनुसार, रिकॉर्ड की जांच–पड़ताल और फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (एफएसएलस) की राय से प्रथम दृष्टया यह साबित हुआ कि मंजाकोट के तत्कालीन ज़ेडईओ शाह नवाज़ खान और एमडीएम का काम देखने वाले तत्कालीन जूनियर असिस्टेंट मोहम्मद फारूक ने अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग किया। उन्होंने आधिकारिक रिकॉर्ड में हेरफेर करके नकली, जाली और मनगढ़ंत इंडेंट और अथॉरिटी लेटर तैयार किए।

जांच में पाया गया कि एमडीएम योजना के लिए आए 256.40 क्विंटल चावल (जिसकी कीमत 8,03,557.60 रुपये थी) का कथित तौर पर गबन किया गया। खाना पकाने के खर्च के तौर पर अतिरिक्त 4,61,578 रुपये का भी कथित तौर पर गबन किया गया, जिससे सरकारी खजाने को कुल 12,65,135.60 रुपये का नुकसान हुआ।

एसीबी ने बताया कि शाह नवाज़ खान की मौत हो चुकी है, इसलिए उनके खिलाफ मुकदमा नहीं चलाया जा सका। आरोपी मोहम्मद फारूक, जो अभी भी सेवा में है, पर मुक. दमा चलाने की मंजूरी सक्षम अधिकारी से ले ली गई है। इसके बाद एसीबी ने 31 अगस्त, 2026 को राजौरी में एंटी–करप्शन के स्पेशल जज की अदालत में फारूक के खिलाफ चार्जशीट पेश की।

अदालत ने सुनवाई की अगली तारीख 29 सितंबर, 2026 तय की है।

मौसम विभागः 1901 ...

रहने की संभावना है।

आईएमडी में मौसम विज्ञान के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र ने एक बयान में कहा कि अभी भूमध्यरेखीय प्रशांत महासागर में मजबूत अल–नीनो की स्थिति बनी हुई है, और मध्य व पूर्वी भूमध्यरेखीय प्रशांत क्षेत्र में समुद्र की सतह का तापमान (एसएसटी) सामान्य से ऊपर बना हुआ है।

उन्होंने कहा, आने वाले महीनों में इन स्थितियों के और मजबूत होने की उम्मीद है। महापात्र के अनुसार, 1901 के बाद से भारत में अगस्त 2026 सबसे गर्म रहा, क्योंकि औसत तापमान 28.01 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

इस महीने के लिए सामान्य औसत तापमान 27.34 डिग्री सेल्सियस है। उन्होंने कहा कि अगस्त 2026 के लिए औसत न्यूनतम तापमान भी 1901 के बाद सबसे अधिक रहा, जो सामान्य 23.68 डिग्री सेल्सियस के मुकाबले 24.36 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया।

आईएमडी ने कहा कि इस महीने में बारिश की कमी भी देखी गई 213.3 मिमी बारिश हुई, जो 2001 के बाद सातव. ीं सबसे कम बारिश थी। सामान्य से कम बारिश का एक मुख्य कारण भूमध्यरेखीय प्रशांत क्षेत्र में मध्यम से मजबूत अल–नीनो की स्थिति का होना था। इसके अलावा, आईएमडी ने कहा कि हालांकि अगस्त के दौरान कम दबाव वाले चार सिस्टम बने और कुल मिलाकर 26 दिनों तक बने रहे, लेकिन उनसे होने वाली बारिश मुख्य रूप से इंडो–गैंगेटिक मैदानी इलाकों तक ही सीमित रही, जिससे बाकी हिस्सों में बारिश की कमी बनी रही।

लद्दाख में दलाई लामा ...

करने का आह्वान किया और कहा कि तिब्बती बौद्धों द्वारा संरक्षित परंपरा का प्रसार जारी रहना चाहिए।

उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि हमें तिब्बत और मुख्य भूमि चीन में बुद्ध की शिक्षाओं के फलने–फूलने के लिए भी प्रार्थना करनी चाहिए दूसरे शब्दों में, उन जगहों पर जहां यह पहले प्रचलित थी लेकिन अब कम हो गई है, और उन जगहों पर जहां यह अभी तक नहीं पहुंची है। उन्होंने कहा, आइए हम सब प्रार्थना करें कि बौद्ध धर्म की जिस परंपरा को हमने संजोकर रखा है, वह जीवित रहे और फलती–फूलती रहे। तिब्बत में हमने एक बहुत ही शुद्ध परंपरा बनाए रखी। कई जगहें ऐसी हैं जहां इस परंपरा ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया है। मैं बुद्ध की शिक्षाओं के निरंतर प्रसार और फलने–फूलने के लिए प्रार्थना करूंगा।

दलाई लामा ने कहा कि बौद्ध धर्म में रुचि लेने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है और उन्होंने हिमालयी क्षेत्र के लोगों की आस्था और भक्ति का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा, षहिमालयी क्षेत्र के लोगोंकृचाहे वे आम लोग हों या भिक्षुकृका इन शिक्षाओं में अटूट विश्वास और श्रद्धा है। हमारी परंपरा बहुत विशाल और गहरी है; आइए हम प्रार्थना करें कि यह चीनी लोगों के बीच भी फले–फूले। उन्होंने बौद्ध अनुयायियों से अपनी मान्यताओं को असल जीवन में उतारने का भी आग्रह किया।

उन्होंने कहा, मैं अपनी साधना को व्यावहारिक रूप से निभाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। आपको भी ऐसा ही करना चाहिए; केवल परंपरा की बातें न करें, बल्कि अपनी क्षमता के अनुसार व्यावहारिक बनें और इन शिक्षाओं को असल जीवन में अपनाएँ। समारोह के दौरान, दलाई लामा ने कई बौद्ध मंत्रों का मौखिक पाठ किया और प्रार्थना की कि बौद्ध धर्म की शिक्षाएँ भारत, चीन, पश्चिमी देशों और अफ्रीका में और अधिक फैलें।

इस समारोह में लंबी उम्र के लिए पारंपरिक प्रार्थनाएँ, भेंट और पाठ शामिल थे, जिनमें दलाई लामा के दो गुरुओं द्वारा रचित अमरता का गीत भी शामिल था। कार्यक्रम का समापन सभी संप्रदायों से परे बौद्ध शिक्षाओं के प्रसार और तिब्बती लोगों तथा बौद्ध परंपरा की सुरक्षा के लिए की गई प्रार्थनाओं के साथ हुआ। बाद में, अपने आवास पर लौटने से पहले दलाई लामा ने वहाँ मौजूद लोगों का हाथ हिलाकर अभिवादन किया।

कश्मीर के मंडलायुक्त ...

बातचीत करें ताकि रेलवे फ्रेट सर्विस के ज़्यादा और सस्ते इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जा सके। उन्होंने ज़ोर दिया कि लंबी दूरी के लिए रेलवे ट्रांसपोर्टेशन का ज्यादा इस्तेमाल किया जाना चाहिए क्योंकि यह बड़ी मात्रा में बाग. वानी उत्पादों के ट्रांसपोर्टेशन के लिए सस्ता और असरदार विकल्प हो सकता है। उन्होंने डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर प्लानिंग एंड मार्केटिंग को यह भी निर्देश दिया कि वे उत्पादों की सुचारू आवाजाही के लिए फल उत्पादकों, व्यापारियों, एसोसिएशन और रेलवे अधिकारियों के बीच बेहतर तालमेल सुनिश्चित करें।

डिविजनल कमिश्नर ने अनंतनाग की जाबलीपोरा मंडी से बागवानी उत्पादों के ट्रांसपोर्टेशन को ज्यादा से ज्यादा करने पर खास ज़ोर दिया। उन्होंने सभी डिप्टी कमिश्नर को यह भी निर्देश दिया कि वे अपने–अपने ज़िलों से रेलवे सर्विस के ज़रिए फलों की खेप के एक निश्चित हिस्से के ट्रांसपोर्टेशन की संभावना तलाशें और उसे आसान बनाएं। रोल–आन/रोल–आफ सर्विस पर चर्चा करते हुए डिविजनल कमिश्नर ने नार्दर्न रेलवे के अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे फल एसोसिएशन के साथ एक जानक. ारीपूर्ण वीडियो शेयर करें। इस वीडियो में ट्रकों के लिए तय तकनीकी पैरामीटर जैसे कि लोड की मंजूर ऊंचाई और दूसरी ज़रूरतों के बारे में बताया जाए, ताकि इसका असरदार इस्तेमाल हो सके।

सड़क मार्ग से फलों के ट्रांसपोर्टेशन के संबंध में कश्मीर के डिविजनल कमिश्नर और आईजीपी ट्रैफिक, कश्मीर दोनों ने फल एसोसिएशन को निर्देश दिया कि वे ट्रक ड्राइवरों को नेशनल हाईवे पर तय लोड लिमिट का पालन करने के बारे में बड़े पैमाने पर जागरूक करें। उन्होंने ज़ोर दिया कि ओवरलोडिंग न केवल तय नियमों का उल्लंघन है बल्कि सड़क सुरक्षा और ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए भी गंभीर खतरा पैदा करती है। अधिकारियों ने चेतावनी दी कि तय भार सीमा से ज्यादा भार ले जाने वाले वाहनों के खिलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

अलग–अलग फल संघों के प्रतिनिधियों ने अपने सुझाव रखे और बागवानी क्षेत्र के लिए ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को मज़बूत करने के लिए लंबे समय तक चलने वाले समाधानों की मांग की, जिसमें फल मंडियों को रेलवे नेटवर्क से बेहतर ढंग से जोड़ना भी शामिल है। प्रतिनिधियों ने फल उद्योग को लगातार सहयोग और सुविधाएँ देने के लिए प्रशासन की तारीफ़ भी की।

जेएंडके कांग्रेस न ..

अहम हिस्सा हैं और अपनी अनिवार्य इंटर्नशिप के दौरान अस्पतालों में बड़ी ज़िम्मेदारियाँ निभाते हैं।

कर्रा ने कहा, ये युवा डॉक्टर अक्सर लंबे और मुश्किल घंटों तक काम करते हैं, जिसमें 36 घंटे की शिफ्ट भी शामिल है। वे पूरी लगन और निष्ठा के साथ मरीज़ों की देखभाल करते हैं और अपनी ड्यूटी निभाते हैं। उन्होंने बताया कि जम्मू–कश्मीर में मेडिकल इंटर्न को दिया जाने वाला स्टाइपेंड देश के कई अन्य हिस्सों की तुलना में काफी कम है। उन्होंने कहा, जब दूसरी जगहों पर समान ज़िम्मेदारियों और काम के घंटों के लिए इंटर्न को बेहतर आर्थिक मदद दी जा रही है, तो हमारे मेडिकल इंटर्न की स्टाइपेंड में उचित बढ़ोतरी की मांग पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए।

कर्रा ने उमर से अपील की कि वे संबंधित अधिकारियों को निर्देश दें कि वे विरोध कर रहे इंटर्न से बात करें, उनकी शिकायतें सुनें और इस मुद्दे के जल्द और संतोषजनक समाधान के लिए काम करें। कांग्रेस नेता ने कहा कि इस चरण में सरकार का सकारात्मक दखल न केवल मेडिकल बिरादरी की जायज़ चिंता को दूर करेगा, बल्कि युवा डॉक्टरों का मनोबल भी बढ़ाएगा, जो अस्पतालों और स्वास्थ्य संस्थानों के कामकाज में अहम योगदान देते हैं।

उन्होंने उम्मीद जताई कि सरकार इस मामले को प्राथमिकता देगी और जम्मू–कश्मीर में मेडिकल इंटर्न के स्टाइपेंड में सार्थक बढ़ोतरी के लिए ज़रूरी कदम उठाएगी, ताकि यह उनकी ज़िम्मेदारियों और देश के अन्य हिस्सों में दिए जा रहे स्टाइपेंड के अनुरूप हो। इंटर्न ने कहा कि बार–बार गुहार लगाने और विरोध–प्रदर्शन करने के बावजूद उनका स्टाइपेंड लगभग सात वर्षों से नहीं बदला है, जबकि रहने का खर्च और कई अन्य राज्यों में इंटर्न को मिलने वाला स्टाइपेंड काफी बढ़ गया है। इंटर्न द्वारा दिखाए गए तुलनात्मक आंकड़ों के अनुसार, ओडिशा 44,319 रुपये के मासिक स्टाइपेंड के साथ सूची में सबसे ऊपर है, इसके बाद पश्चिम बंगाल 43,099 रुपये और असम 35,000 रुपये के साथ हैं।

कर्नाटक 30,000 रुपये देता है, जबकि केरल 27,300 रुपये और दिल्ली और मेघालय प्रत्येक 26,300 रुपये देते हैं।

तेलंगाना में स्टाइपेंड 25,900 रुपये है, जबकि अरुणाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश प्रत्येक 25,000 रुपये देते हैं। तमिलनाडु का स्टाइपेंड लगभग 25,000 रुपये है, इसके बाद हरियाणा 24,310 रुपये और आंध्र प्रदेश लगभग 21,840 रुपये के साथ हैं। गुजरात, बिहार, गोवा और हिमाचल प्रदेश में स्टाइपेंड लगभग 20,000 रुपये प्रति माह है, जबकि पुडुचेरी 18,000 रुपये देता है।

सुरक्षा बलों ने शोपियां म ...

के 60 राउंड गोला–बारूद, एक पिस्तौल, एक ग्रेनेड और 9 एमएम के 6 राउंड गोला–बारूद शामिल हैं। अधिकारियों ने आगे कहा, बरामद हथियारों के स्रोत और उनके संभावित इस्तेमाल का पता लगाने के लिए आगे की जांच शुरू कर दी गई है।

Created by Universal Document Converter

मेघ मंडल समाज सामुदायिक भवन में एक दिवसीय निशुल्क मेडिकल कैंप का किया गया आयोजन

आरएस पुरा। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन मेडिकल स्टूडेंट नेटवर्क की तरफ से आचार्य श्री चंद्र हॉस्पिटल जम्मू के सहयोग साथ वार्ड नंबर पांच स्थित मेघ मंडल समाज सामुदायिक भवन में एक दिवसीय निशुल्क मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया जिसमें विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम ने लोगों के स्वास्थ्य की जांच की तथा उनमें निशुल्क दवाइयां वितरित की। मेघ मंडल समाज के प्रधान गारू राम उत्तम के प्रयासों से आयोजित किए गए इस एक दिवसीय चिकित्सा शिविर के दौरान पूर्व मंत्री चौधरी श्याम लाल तथा विधायक प्रोफेसर गारू राम भगत मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे जिन्होंने चिकित्सा शिविर का उद्घाटन किया और क्षेत्र में इस तरह का मेडिकल कैंप आयोजित करने के लिए मेघ मंडल समाज के सदस्यों के अलावा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन मेडिकल स्टूडेंट नेटवर्क की प्रशंसा की और कहा कि इस तरह के मेडिकल कैंप लोगों के लिए काफी लाभदायक सिद्ध होते हैं और एक ही स्थान पर लोगों को हर विशेषज्ञ डॉक्टर की सुविधा मिल रही है।

पूर्व मंत्री चौधरी श्याम लाल ने कहा कि इस मेडिकल कैंप में हर किस्म की बीमारी की जांच हो रही है और लोगों को निशुल्क दवाइयां दी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि मेघ मंडल समाज की तरफ से समय–समय पर इस तरह के सामाजिक कार्यों को किया जाता है। वही विधायक प्रोफेसर गारू राम भगत ने कहा कि इस तरह के मेडिकल कैंप लोगों के लिए काफी लाभदायक सिद्ध होते हैं। इस मौके पर पूर्व नगर अध्यक्ष सतपाल पप्पी, पूर्व उपाध्यक्ष किशोर शर्मा, पूर्व पार्षद राजकुमार, देविंदर शर्मा, शशि उत्तम, संजीव कुमार, हजूरी सिंह, पप्पू चौधरी तथा अशोक कुमार सहित बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे।

सुरेंद्र सिंह टोनी बने रामगढ़ तहसील से जाट बिरादरी के प्रधान

चौधरी यशपाल को विजयपुर तथा रतन चौधरी को दी गई जिला सांबा की जिम्मेदारी

रामगढ़। जाट बिरादरी की तरफ से रामगढ़ क्षेत्र में आयोजित एक महत्वपूर्ण बैठक के दौरान बिरादरी की तरफ से बिरादरी के तहसील प्रधान बनाए गए। पूर्व जिला विकास परिषद सदस्य अनीता चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित जाट बिरादरी की इस महत्वपूर्ण बैठक के दौरान जाट नेता शमशेर चौधरी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे जिनकी मजबूती में तहसील रामगढ़ से सुरेंद्र सिंह टोनी को जाट बिरादरी का तहसील प्रधान बनाया गया। इसके अलावा तहसील विजयपुर के लिए चौधरी यशपाल तथा जिला सांबा से पूर्व कैप्टन रतन चौधरी को जाट बिरादरी का तहसील प्रधान नियुक्त किया गया। इस मौके पर बिरादरी के लोगों द्वारा नियुक्त हुए तीनों

तहसील प्रधान का हार पहना कर जोरदार तरीके के साथ स्वागत किया गया और उन्हें नई जिम्मेदारी मिलने पर मुबारकबाद दी गई। इस मौके पर बैठक को संबोधित करते हुए जाट नेता शमशेर चौधरी ने कहा कि जाट बिरादरी के लोगों के समक्ष आ रही समस्याओं को दूर करने के मकसद से लगातार बिरादरी की तहसील स्तर पर इकाइयां गठन की जा रहे हैं और उसी के चलते आज तहसील सांबा रामगढ़ एवं विजयपुर के तहसील प्रधान बनाए गए हैं और आने वाले दिनों में अन्य तहसीलों में भी बिरादरी के तहसील प्रधान नियुक्त किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि बिरादरी को एकजुट करने के मकसद से लगातार जम्मू कश्मीर के हर एक क्षेत्र में बिरादरी की बैठकों का आयोजन भी किया जा रहा है। इस मौके पर तहसील प्रधान नियुक्त होने पर सुरेंद्र सिंह टोनी, चौधरी रतनलाल तथा यश चौधरी ने बिरादरी के लोगों का धन्यवाद किया और कहा कि बिरादरी की तरफ से उन्हें जो जिम्मेदारी दी गई है उसे पर वह खरा करने के लिए पूरी जिम्मेदारी तथा मेहनत के साथ कार्य करेंगे कार्यक्रम के दौरान जाट नेता डीएसपी सुरेंद्र पाल सिंह, चौधरी कमल सिंह, प्रदीप चौधरी, पूर्व सरपंच विजय चौधरी, तहसील प्रधान सुचौतगढ़ सरदार ओंकार सिंह, जसवीर सिंह समोत्रा, तहसील प्रधान आरएस पुरा दर्शन चौधरी, राजेश चौधरी, रामपाल चौधरी सहित बड़ी संख्या में बिरादरी के लोग मौजूद रहे।

बीएसएनएल की सुस्त सेवा से उपभोक्ता त्रस्त, छह माह से टावर खराब

रामगढ़ (गुरदीप कुमार)। रामगढ़ क्षेत्र के गांव केसों में

बीएसएनएल की मोबाइल और इंटरनेट सेवाएं लंबे समय से सुस्त पड़ी हैं। नेटवर्क की स्थिति इतनी खराब है कि लोगों को फोन करने के लिए भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जबकि इंटरनेट सेवा की बात करना भी मुश्किल है। स्थानीय लोगों ने बताया कि बेहतर नेटवर्क की उम्मीद में कई लोगों ने अपनी एयरटेल सिम को पोर्ट करवाकर बीएसएनएल में बदलवाया था, लेकिन अब उन्हें खराब नेटवर्क के कारण परेशानी उठानी पड़ रही है। लोगों का कहना है कि हर महीने रिचार्ज करवाने के बावजूद सेवा बेहद खराब है। अजय, अवतार, सुभाष, रवि, राकेश आदि ने बताया कि रजवाल में लगा बीएसएनएल का टावर पिछले करीब छह महीने से खराब पड़ा है। इसकी वजह से केसों सहित आसपास के गांवों में भी नेटवर्क प्रभावित हो रहा है। लोगों का आरोप है कि कई बार संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को समस्या से अवगत करवाने के बावजूद टावर को ठीक नहीं किया गया। ग्रामीणों ने बीएसएनएल के उच्च अधिकारियों से मांग की है कि खराब पड़े टावर को जल्द दुरुस्त करवाकर क्षेत्र में मोबाइल और इंटरनेट सेवाएं सुचारु की जाएं।

एसएमवीडीएसबी के सीईओ ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को किया सम्मानित

कटरा (रोहित शर्मा)। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) श्री सचिन कुमार वैश्य ने श्री माता वैष्णो देवी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के खिलाड़ियों को विभिन्न खेलों में शानदार प्रदर्शन करने पर सम्मानित किया। खिलाड़ियों ने एथलेटिक्स, फुटबॉल और जूडो में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर श्राइन बोर्ड का नाम रोशन किया है।

जम्मू विश्वविद्यालय के एथलेटिक्स ट्रैक पर आयोजित 24वीं जम्मू–कश्मीर यूटी एथलेटिक्स चौंपियनशिप में श्री माता वैष्णो देवी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के खिलाड़ियों ने विभिन्न आयु वर्गों में शानदार प्रदर्शन किया। जम्मू–कश्मीर एमेच्योर एथलेटिक्स एसोसिएशन द्वारा एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के तत्वावधान में तथा जम्मू–कश्मीर स्पोर्ट्स

काउंसिल के सहयोग से आयोजित इस प्रतियोगिता में केंद्र शासित प्रदेश के 800 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया।

इस अवसर पर सीईओ ने श्री माता वैष्णो देवी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की फुटबॉल टीम को भी सम्मानित किया, जिसने राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर आयोजित मुकाबले में खेलो इंडिया सेंटर, ऊधमपुर की टीम को हराकर जीत दर्ज की। विजेता टीम को ट्रॉफी प्रदान कर उसके शानदार प्रदर्शन की सराहना की गई।

खिलाड़ियों को बधाई देते हुए सीईओ सचिन कुमार वैश्य ने कहा कि खिलाड़ियों की सफलता उनकी मेहनत, अनुशासन और समर्पण का परिणाम है। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों की उपलब्धियां श्री माता वैष्णो देवी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में विकसित हो रही खेल संस्कृति को दर्शाती हैं। उन्होंने खिलाड़ियों को भविष्य में भी बेहतर प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जम्मू–कश्मीर तथा श्राइन बोर्ड का नाम रोशन करने के लिए प्रेरित किया।

सीईओ ने जूडो कोच श्री दानिश शर्मा को भी प्रतिष्ठित हाई–लेवल टेक्निकल कोर्स फॉर कोचेज हासिल करने पर बधाई दी। यह पाठ्यक्रम अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति और अंतरराष्ट्रीय जूडो महासंघ द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था। सीईओ ने इसे कोच की पेशेवर क्षमता और युवा खिलाड़ियों को तैयार करने के प्रति उनकी प्रतिबद्धता की महत्वपूर्ण पहचान बताया।

उल्लेखनीय है कि श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष एवं जम्मू–कश्मीर के उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा के नेतृत्व में खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। श्री माता वैष्णो देवी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को आधुनिक सुविधाओं और विश्वस्तरीय प्रशिक्षण संसाधनों से युक्त सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जा रहा है, ताकि युवा खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकें।

इस अवसर पर अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री आलोक कुमार मौर्य, संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री सतीश कुमार शर्मा, सहायक मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री ध्रुव गुप्ता सहित कोच, खिलाड़ी और श्राइन बोर्ड के अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

जन्माष्टमी को लेकर कटड़ा के मंदिरों में तैयारियां तेज, सजने लगे देवालय

कटरा (रोहित शर्मा)। शुक्रवार को मनाए जाने वाले पवित्र श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर्व को लेकर विश्व प्रसिद्ध तीर्थस्थल मां वैष्णो देवी भवन से लेकर आधार शिविर कटड़ा तक मंदिरों में सजावट और तैयारियों का दौर शुरू हो गया है। विभिन्न मंदिर कमेटियों ने पर्व को लेकर धार्मिक कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार कर तैयारियां तेज कर दी हैं।

कटड़ा के प्रमुख ऐतिहासिक रघुनाथ मंदिर, प्रसिद्ध शिव दर्शन मंदिर, महालक्ष्मी मंदिर, धार्मिक भूमिका मंदिर, अर्धकुंवारी मंदिर, चरण पादुका मंदिर, बाणगंगा मंदिर, टी गार्डन मंदिर, बिजली घर मंदिर, नौ देवीयां मंदिर सहित अन्य मंदिरों में रंग–रोगन और सजावट का कार्य जोर–शोर से चल रहा है। मंदिरों को आकर्षक ढंग से सजाने के साथ जन्माष्टमी पर विशेष पूजा–अर्चना, भजन–कीर्तन और जागरण सहित विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

विश्व प्रसिद्ध मां वैष्णो देवी भवन में भी जन्माष्टमी पर्व को लेकर विशेष तैयारियां की जा रही हैं। मां वैष्णो देवी की प्राचीन पवित्र गुफा के प्रांगण स्थित अटका स्थल को भव्य रूप से सजाया जाएगा। यहां सुंदर झूले में भगवान श्रीकृष्ण के बाल स्वरूप को विराजमान किया जाएगा। पर्व के दौरान पुजारियों और पंडितों द्वारा भजन–कीर्तन एवं जागरण का आयोजन किया जाएगा। भगवान श्रीकृष्ण को छप्पन भोग अर्पित करने के बाद श्रद्धालुओं में प्रसाद वितरित किया जाएगा।

कटड़ा के प्रसिद्ध शिव दर्शन मंदिर के प्रधान शमी गंडोत्रा ने बताया कि जन्माष्टमी के अवसर पर मंदिर में भगवान श्रीकृष्ण, राधा–कृष्ण, राम दरबार, शिव परिवार और वीर हनुमान की भव्य सजावट की जाएगी। शाम के समय मंदिर प्रांगण में विशेष जागरण आयोजित होगा, जिसमें प्रसिद्ध गायक सुरेश अपनी मधुर आवाज में भगवान श्रीकृष्ण के भजन प्रस्तुत करेंगे। मध्य रात्रि में भगवान श्रीकृष्ण की विधि–विधान से पूजा–अर्चना की जाएगी और छप्पन भोग लगाया जाएगा। इसके बाद श्रद्धालुओं में प्रसाद वितरित किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि जन्माष्टमी पर मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ने की संभावना को देखते हुए सुरक्षा एवं व्यवस्था के विशेष प्रबंध किए जा रहे हैं। मंदिर परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखी जाएगी और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए स्वयंसेवकों की तैनाती भी की जाएगी।

इसी तरह कटड़ा के अन्य प्रमुख मंदिरों की कमेटियों ने भी जन्माष्टमी पर्व को धार्मिक एवं भव्य तरीके से मनाने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। वहीं, नगरवासियों ने भी अपने–अपने घरों में स्थापित मंदिरों की साफ–सफाई और सजावट का कार्य शुरू कर दिया है। जन्माष्टमी के अवसर पर नगर के विभिन्न स्थानों पर व्रत सामग्री तथा प्रसाद के भंडारे लगाने की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं।

गांव केरन स्थित श्री गुरु रविदास गुरुद्वारा की भूमि को गुरुद्वारा के नाम पर आवंटित करे सरकारः दर्शन राणा

जम्मू। जम्मू नॉर्थ विधानसभा क्षेत्र के अधीन

आते गांव केरन में बहुजन समाज पार्टी के जम्मू कश्मीर अध्यक्ष दर्शन राणा की अध्यक्षता में एक जनसभा का आयोजन किया गया जिसमें स्थानीय मुद्दों के साथ–साथ जम्मू कश्मीर सरकार से मांग की गई की गांव केरन में श्री गुरु रविदास गुरुद्वारा की लगभग 4 कनाल जमीन भवन के नाम आवंटित की जाए ताकि श्रद्धालुओं की पुरानी मांग पूरी हो सके। इस मौके पर बैठक को संबोधित करते हुए बसपा के जम्मू कश्मीर अध्यक्ष दर्शन राणा ने कहा कि जम्मू प्राधिकरण की तरफ से लगातार श्री गुरु रविदास भवन के साथ छेड़छाड़ की जा रही है जिसे लेकर लोगों में काफी गुस्सा है। उन्होंने कहा कि अगर भविष्य में किसी तरह की भी कोई छेड़छाड़ हुई तो उसके खिलाफ बड़ा आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से मांग करते हुए कहा कि श्री गुरु रविदास भवन केरन की भूमि को जल्द से जल्द श्री गुरु रविदास गुरुद्वारा के नाम आवंटित किया जाए। उन्होंने कहा कि श्री गुरु रविदास गुरुद्वारा के साथ लोगों की आस्था जुडी हुई है और ऐसे में सरकार को जल्द से जल्द लोगों की आस्था को ध्यान में रखते हुए भूमि को गुरुद्वारा के नाम आवंटित किया जाना चाहिए। इस मौके पर बसपा के प्रदेश उपाध्यक्ष चरणजीत चरगोत्रा ने कहा कि उनकी पार्टी स्थानीय लोगों के साथ खड़ी है और जल्द से जल्द अगर सरकार ने इस मांग को पूरा नहीं किया तो आने वाले दिनों में इस मुद्दे को लेकर आंदोलन चलाया जाएगा जिसकी जिम्मेदारी सरकार तथा संबंधित विभाग की होगी। जनसभा के दौरान पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष कृष्ण लाल, कार्यालय सचिव रतन लाल सहित अन्य लोगों ने भी अपने–अपने विचार रखे।

चाइनीज मांझे के खिलाफ विजयपुर पुलिस की कार्रवाई, दुकानों में की गई जांच

विजयपुर। चाइनीज मांझे (गड्डू डोर) की बिक्री और भंडारण को लेकर विजयपुर पुलिस द्वारा जांच अभियान चलाया गया। थाना प्रभारी विजयपुर परवेज अहमद के दिशा–निर्देशों पर पुलिस अधिकारियों ने विजयपुर क्षेत्र की विभिन्न दुकानों की जांच की और दुकानदारों से चाइनीज मांझे की बिक्री एवं भंडारण न करने की हिदायत दी।

पुलिस द्वारा यह कार्रवाई चाइनीज मांझे से लगातार सामने आ रही चोट की घटनाओं को देखते हुए की गई है। चाइनीज मांझा आम लोगों, दोपहिया वाहन चालकों और राहगीरों के लिए गंभीर खतरा बन सकता है। पुलिस ने दुकानदारों को स्पष्ट निर्देश दिए कि यदि किसी दुकान पर प्रतिबंधित चाइनीज मांझा पाया गया या उसकी बिक्री की जा रही हो तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

विजयपुर पुलिस ने लोगों से भी अपील की है कि वे चाइनीज मांझे का इस्तेमाल न करें और इसकी बिक्री या उपलब्धता की जानकारी मिलने पर पुलिस को सूचित करें। पुलिस का कहना है कि क्षेत्र में इस तरह की जांच आगे भी जारी रहेगी।

वो क्लब गांधरवां, अखनूर ने आयोजित की तीन दिवसीय बाल रंगमंच कार्यशाला

बच्चों ने प्रस्तुत किया देशभक्ति नाटक 'ऑपरेशन सिंदूर'

अखनूर (मोहन सिंह)। वो क्लब गांधरवां, अखनूर की ओर से लिटिल पर्ल्स प्ले वे स्कूल, मंड्रियां में तीन दिवसीय बाल रंगमंच कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्देश्य बच्चों में रंगमंच के प्रति रुचि पैदा करने के साथ–साथ उनमें अभिनय, अभिव्यक्ति, आत्मविश्वास और अनुशासन की भावना विकसित करना रहा।

कार्यक्रम में स्कूल के एम.डी. रविंद्र शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे जबकि समाजसेविका एवं कवयित्री कोमल शर्मा ने विशिष्ट अतिथि के रूप में शिरकत की। कार्यक्रम की अध्यक्षता स्कूल की प्रधानाचार्या श्रीमती प्रीति शर्मा ने की।

कार्यशाला का निर्देशन अर्चना शर्मा एवं प्रीति शर्मा, प्ले डायरेक्टर्स, ने किया। इस दौरान जसबीर सिंह ने बच्चों को रंगमंच और अभिनय की विभिन्न बुनियादी तकनीकों का प्रशिक्षण दिया तथा

नियमित अभ्यास, समर्पण और भाव–भंगिमा के महत्व पर जोर दिया।

तीन दिवसीय कार्यशाला के दौरान बच्चों द्वारा देशभक्ति पर आधारित नाटक 'ऑपरेशन सिंदूर' तैयार किया गया, जिसकी अंतिम प्रस्तुति लिटिल पर्ल्स प्ले वे स्कूल, मंड्रियां के परिसर में दी गई। बच्चों की शानदार प्रस्तुति ने उपस्थित दर्शकों को प्रभावित किया और सभी ने उनकी प्रतिभा एवं आत्मविश्वास की सराहना की।

मुख्य अतिथि सहित उपस्थित दर्शकों ने वो क्लब द्वारा इस प्रकार की कार्यशालाओं को लगातार आयोजित किए जाने की मांग की, ताकि बच्चों को छोटी उम्र से ही रंगमंच से जोड़ा जा सके और उनकी रचनात्मक प्रतिभा को सही दिशा मिल सके।

कार्यक्रम की शुरुआत वो क्लब के अध्यक्ष श्री बलविंदर सिंह पवार के स्वागत भाषण से हुई। उन्होंने सभी अतिथियों एवं उपस्थित लोगों का स्वागत करते हुए इस देशभक्ति नाटक को सफल बनाने में सहयोग देने वाली पूरी टीम का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यक्रम बच्चों में देशभक्ति, आत्मविश्वास और सामाजिक जागरूकता की भावना को मजबूत करते हैं।

अर्चना शर्मा ने कार्यक्रम का संचालन किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि रविंद्र शर्मा एवं विशिष्ट अतिथि श्रीमती कोमल शर्मा ने भी अपने विचार रखे और बच्चों के शानदार प्रदर्शन की सराहना की। कार्यक्रम के अंत में एडवोकेट नरेश कुमार रैना, लीगल एडवाइजर वो क्लब, ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया। कार्यशाला में भाग लेने वाले बच्चों एवं अतिथियों को प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्ह प्रदान किए गए। कार्यक्रम का समापन हाई–टी के साथ हुआ।

Created by Universal Document Converter

सम्पादकीय

खट्टा–मीठा

भारत में चीनी की कमी एक ऐसी पॉलिसी से जुड़ी समस्या को सामने ला रही है जो सिर्फ मिठाइयों की कीमत से कहीं ज़्यादा बड़ी है। फिलहाल चिंता इस बात की है कि क्या त्योहारों के मौसम में उचित कीमत पर काफी चीनी मिल पाएगी। इससे भी ज़्यादा अहम सवाल यह है कि क्या भारत की एनर्जी सिक्योरिटी (ऊर्जा सुरक्षा) की कोशिशें फूड सिक्योरिटी (खाद्य सुरक्षा) बनाए रखने की जिम्मेदारी से टकराने लगी हैं। चीनी का उत्पादन पहले के अनुमानों से काफी कम रहा है, जबकि घरेलू खपत देश के कुल उत्पादन के बराबर ही बनी हुई है।

फिर भी, कमी का पता चलने से पहले भारत ने बड़े पैमाने पर निर्यात की इजाजत दी और अब दस साल में पहली बार दस लाख टन तक चीनी के ड्यूटी–फ्री आयात का रास्ता खोल दिया है। यह बदलाव चौंकाने वाला हैरू जो देश चीनी का निर्यात करता था, वह अब घरेलू सप्लाई बनाए रखने के लिए उसे आयात कर रहा है। मौसम भी इसकी एक वजह है। गन्ने की फसल पानी पर बहुत ज़्यादा निर्भर करती है, और अनियमित बारिश, सूखे के दौर, बहुत ज़्यादा बारिश और बीमारियों ने अहम उत्पादक राज्यों में फसल को नुकसान पहुँचाया है। जमाखोरी और सट्टेबाजी वाली खरीद ने भी कीमतों में उछाल को और बढ़ा दिया होगा। लेकिन ये बातें पॉलिसी की नाकामी को पूरी तरह नहीं समझातीं। जब उत्पादन के अनुमान इतने ज़्यादा आशावादी हो सकते हैं कि उसी सीजन में निर्यात की मंजूरी दी जाए और आयात जरूरी हो जाए, तो फोरकास्टिंग सिस्टम की विश्वसनीयता पर ही सवाल उठना चाहिए। यहीं पर बहस में ₹20 का जिक्र आता है।

यह कहना बहुत आसान होगा कि चीनी की कमी की वजह इथेनॉल है। सरकार का कहना है कि इथेनॉल के लिए इस्तेमाल होने वाले गन्ने का हिस्सा कम हुआ है। ₹20 एनर्जी सिक्योरिटी के सही मकसद भी पूरे करता है। लेकिन ₹20 ने उसी कृषि संसाधन के लिए एक और माँग पैदा कर दी है। गन्ना या तो चीनी उत्पादन में काम आ सकता है या इथेनॉल उत्पादन में। अच्छी फसल वाले सालों में, इस ट्रेड–ऑफ को संभाला जा सकता है। लेकिन खराब फसल वाले साल में, लाखों टन चीनी के बराबर गन्ना इथेनॉल में लगाने से उत्पादन में आने वाले झटके को सहने की क्षमता कम हो जाती है। यह फर्क मायने रखता है। हो सकता है कि ₹20 इस संकट की वजह न हो, लेकिन इसने सप्लाई के गलत अनुमान के नतीजों को और गंभीर बना दिया है। इसलिए भारत को फूड सिक्योरिटी, एनर्जी पॉलिसी और कृषि व्यापार को अलग–अलग चीजों के तौर पर देखना बंद करना होगा।

भारत गन्ने को ईंधन के लिए इस्तेमाल करने को बढ़ावा नहीं दे सकता, आशावादी अनुमानों के आधार पर निर्यात की इजाजत नहीं दे सकता और फिर इन नीतियों के आपसी असर को समझे बिना कमी होने पर आयात का सहारा नहीं ले सकता। इससे पता चलता है कि जिम्मेदार लोगों का ध्यान मुख्य मुद्दे से हट गया था। इसका जवाब जरूरी नहीं कि ई20 को छोड़ना ही हो। इसका जवाब है बदलाव की प्रक्रिया में लचीलापन लाना। जब चीनी उत्पादन का अनुमान तेजी से गिरे, तो इथेनॉल के आवंटन में बदलाव की गुंजाइश होनी चाहिए। जब स्टॉक पहले से तय सुरक्षित सीमा के करीब पहुँच जाए, तो निर्यात पर अपने–आप ज़्यादा पाबंदियाँ लग जानी चाहिए।

निर्यात की मंजूरी बढ़ाने से पहले फसल के अनुमानों की स्वतंत्र रूप से जाँच होनी चाहिए। और चीनी के रणनीतिक भंडार को देश के दूसरे खाद्य–सुरक्षा बफर की तरह ही गंभीरता से लिया जाना चाहिए। बड़ी चेतावनी साफ हैरू ऊर्जा सुरक्षा को इस तरह से हासिल नहीं किया जा सकता कि मान लिया जाए कि खाद्य सुरक्षा की कोई 'अपॉर्चुनिटी कॉस्ट' (मौका गंवाने की कीमत) नहीं है। भारत को ई20 को इस तरह से लागू करने की जरूरत है कि अनुमान, व्यापार नीति या कृषि योजना में हुई गलतियों की कीमत रसोई को न चुकानी पड़े।

नेपाल की त्रासदी से भारत को सबक लेने की जरूरत

ललित गर्ग

नेपाल में 26 अगस्त 2026 को आई विनाशकारी बाढ़ और हिमस्खलन ने एक बार फिर यह कठोर सत्य सामने ला दिया है कि प्रकृति के साथ खिलवाड़ और पहाड़ों की संवेदनशीलता की अनदेखी मानव सभ्यता के लिए कितनी भारी पड़ सकती है। भोटेकोशी नदी तंत्र में ग्लेशियर के बड़े हिस्से के टूटने, बर्फ–पत्थरों के विशाल मलबे के नीचे आने और नदी के प्रवाह में अस्थायी अवरोध बनने के बाद अचानक बाढ़ का जो रौद्र एवं भयावह रूप सामने आया, उसने नेपाल और चीन के तिब्बती क्षेत्र में भारी तबाही मचाई। 29 अगस्त तक उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार नेपाल में 579 और तिब्बत में 6 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है तथा लगभग 2,482 लोग लापता बताए जा रहे हैं। हजारों लोगों को बचाया गया है, लेकिन दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों और लगातार बने नए खतरे के कारण राहत एवं बचाव कार्य अभी भी चुनौतीपूर्ण है। यह घटना केवल नेपाल की प्राकृतिक त्रासदी नहीं है, बल्कि पूरे हिमालयी क्षेत्र के लिए भविष्य का भयावह संकेत है।

प्रारंभिक वैज्ञानिक आकलन बताते हैं कि ग्लेशियर का हिस्सा टूटकर नीचे गिरा, जिससे बर्फ, चट्टान, मिट्टी और मलबे का विशाल प्रवाह पैदा हुआ। इसने नदी के प्रवाह को अवरुद्ध किया और बाद में जमा पानी तथा मलबे के दबाव से अचानक विनाशकारी बाढ़ आई। विशेषज्ञों के अनुसार ऐसे घटनाक्रम को केवल सामान्य बाढ़ कहना भूल होगी, यह ग्लेशियर, भूस्खलन, मलबा–प्रवाह और नदी–बाढ़ जैसे अनेक खतरों के एक साथ सक्रिय होने वाली 'बहु–आपदा' का उदाहरण है।

इस त्रासदी का सबसे बड़ा संदेश जलवायु परिवर्तन से जुड़ा है। हिमालय केवल बर्फ से ढकी पर्वतमाला नहीं, बल्कि एशिया की जल–सुरक्षा का आधार है। तापमान बढ़ने के साथ ग्लेशियर तेजी से पीछे हट रहे हैं और अनेक नई ग्लेशियर झीलें बन रही हैं। इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट के अनुसार हिंदूकुश हिमालय ग्लेशियरों और पर्वतीय भूभाग को अस्थिर कर रहा है, जिससे ऐसी घटनाओं की संभावित तीव्रता और व्यापकता बढ़ सकती है। वैज्ञानिकों ने भी इस बात पर सावधानी बरती है कि किसी एक घटना को सीधे जलवायु परिवर्तन का परिणाम घोषित करने के बजाय दीर्घकालिक जलवायु और भूगर्भीय बदलावों को साथ देखकर समझना चाहिए।

नेपाल की घटना भारत के लिए भी गहरी चेतावनी है। इस चेतावनी से सीख लेने की जरूरत है। उत्तराखंड की केदारनाथ त्रासदी, 2021 की ऋषिगंगा आपदा और हिमालयी राज्यों में बार–बार आने वाली बाढ़, भूस्खलन एवं बादल फटने की घटनाएं पहले ही बता चुकी हैं कि पहाड़ों की सहनशीलता असीमित नहीं है। हिमालय में सड़कें, सुरंगें, जलविद्युत परियोजनाएं, होटल, बस्तियां और अन्य निर्माण आवश्यकताओं को पूरा करने के नाम पर तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या इनके लिए पर्वतीय पर्यावरण की वहन क्षमता का पर्याप्त आकलन हो रहा है? विकास जरूरी है, मगर ऐसा विकास जो पहाड़ों को खोखला करके ही संभव हो, अंतत मानव जीवन और स्वयं विकास दोनों के लिए संकट बन सकता है। आज सबसे बड़ी आवश्यकता 'आपदा के बाद राहत' से आगे बढ़कर 'आपदा से पहले तैयारी' की है। अत्याधुनिक सैटेलाइट निगरानी, ड्रोन, रडार, नदी सेंसर, ग्लेशियर और ग्लेशियर झीलों की निरंतर निगरानी तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित पूर्वानुमान प्रणालियों को हिमालयी क्षेत्र में व्यापक स्तर पर विकसित करना होगा। शुरुआती चेतावनी प्रणाली केवल राजधानी या प्रशासनिक केंद्र तक सीमित न रहे, बल्कि पहाड़ के अंतिम गांव तक मोबाइल संदेश, सायरन, रेडियो और स्थानीय स्वयंसेवी तंत्र के माध्यम से पहुंचे। नेपाल में वर्तमान त्रासदी के बाद भी एक और संभावित झील के फटने की आशंका ने स्पष्ट कर दिया है कि एक आपदा समाप्त होते ही दूसरी आपदा का खतरा पैदा हो सकता है।

नदियां राजनीतिक सीमाओं को नहीं पहचानतीं। भोटेकोशी जैसी सीमापार नदी प्रणालियों के लिए नेपाल, चीन, भारत और अन्य हिमालयी देशों के बीच वास्तविक समय में जल–प्रवाह, वर्षा, भूस्खलन, ग्लेशियर झील और हिमस्खलन संबंधी सूचनाओं का आदान–प्रदान आवश्यक है। किसी एक देश के पास उपलब्ध महत्वपूर्ण चेतावनी दूसरे देश के नागरिकों की जान बचा सकती है। अत हिमालय के लिए एक साझा क्षेत्रीय आपदा–पूर्व चेतावनी नेटवर्क विकसित किया जाना चाहिए। भारत को इस दिशा में अपने हिमालयी राज्यों के लिए अलग 'माउंटेन सेफ्टी पॉलिसी' पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क या सुरंग बनाने से पहले भूगर्भीय जोखिम, जलधाराओं के प्राकृतिक मार्ग, भूस्खलन की संभावना और स्थानीय पारिस्थितिकी का वैज्ञानिक मूल्यांकन अनिवार्य होना चाहिए। अंधाधुंध पेड़ कटाई, नदी किनारे अनियोजित निर्माण, पहाड़ों की अनावश्यक कटाई और पर्यटन के नाम पर अत्यधिक दबाव को नियंत्रित करना होगा। स्थानीय समुदायों को आपदा प्रबंधन की पहली पंक्ति बनाना होगा, क्योंकि किसी भी संकट में सबसे पहले वही लोग प्रभावित होते हैं और वही सबसे पहले सहायता भी कर सकते हैं।

दुनिया को जापान, स्विट्जरलैंड और अन्य पर्वतीय देशों से आपदा–प्रबंधन, भवन सुरक्षा, पूर्व चेतावनी और स्थानीय प्रशिक्षण की तकनीक सीखनी चाहिए। हिमालय को केवल पर्यटन और आर्थिक विकास का क्षेत्र मानना अब पर्याप्त नहीं है इसे एक जीवित, संवेदनशील और अत्यंत नाजुक पारिस्थितिक तंत्र के रूप में देखना होगा। प्रकृति को नियंत्रित करने की मनुष्य की महत्वाकांक्षा जितनी बढ़ेगी, प्रकृति का प्रतिरोध भी उतना ही भयावह हो सकता है। नेपाल की त्रासदी इसलिए केवल शोक मनाने का अवसर नहीं, बल्कि आत्ममंथन का क्षण है। हमें यह समझना होगा कि पहाड़ों को जीतना नहीं, उनके साथ जीना सीखना होगा। विकास की गति को प्रकृति की क्षमता के अनुरूप करना, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करना, वैज्ञानिक चेतावनियों को गंभीरता से लेना और सीमापार सहयोग बढ़ाना ही भविष्य की राह है। यदि इस त्रासदी से भारत और दुनिया ने समय रहते सबक ले लिया, तो नेपाल में बहा हुआ पानी केवल विनाश की कहानी नहीं रहेगा, वह आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित रखने की चेतावनी और नई पर्यावरणीय चेतना का संदेश भी बनेगा।

बिहार के 'सहयोग मॉडल' से बाकि राज्यों को भी सीखने की जरूरत

संजीव कुमार मिश्र

क्या किसी सरकारी स्कूल या हॉस्टल में गंदा पानी, खराब खाना या बिजली की किल्लत जैसी रोजमर्रा की समस्याओं का समाधान 30 दिन के भीतर पाना संभव है? जहां देश के अधिकांश राज्यों में छात्र ऐसी बुनियादी सुविधाओं के लिए महीनों प्रशासनिक चक्कर काटने या सड़कों पर उतरने को मजबूर होते हैं, वहीं बिहार सरकार ने एक पारदर्शी ऑनलाइन व्यवस्था से इस धारणा को बदलने की कोशिश की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी द्वारा शुरू की गई इस नई पहल ने छात्र शिकायतों के निपटारे का एक ऐसा मॉडल पेश किया है, जिसकी गूंज अब देश भर में सुनाई दे रही है।

छात्रों की शिकायतें अक्सर लंबे समय तक अनसुलझी रहती हैं, इसकी बड़ी वजह प्रशासनिक प्रक्रिया की जटिलता है। किसी छात्र को हॉस्टल की सफाई, भोजन की गुणवत्ता, बिजली–पानी या फीस से जुड़ी दिक्कत होने पर पहले वार्डन, फिर प्रिंसिपल और जरूरत पड़ने पर जिला शिक्षा कार्यालय तक जाना पड़ता है। इस प्रक्रिया में न तो कोई तय समयसीमा होती है और न ही स्पष्ट जवाबदेही तय होती है, जिस वजह से छोटी शिकायतें भी हफ्तों–महीनों तक लंबित रह जाती हैं।

बिहार सरकार के विद्यार्थी सहयोग पोर्टल की खासियत यह है कि शिकायत दर्ज कराने के लिए दो अलग कैटेगरी बनाई गई है कृ पहली, शैक्षणिक संस्थान यानी विद्यालय, महाविद्यालय या विश्वविद्यालय से संबंधित विद्यार्थियों के लिए, और दूसरी, छात्रावास यानी हॉस्टल में रहने वाले विद्यार्थियों के लिए। पोर्टल के होमपेज पर ही यह दोनों विकल्प दिए गए हैं, जिससे छात्र सही कैटेगरी चुनकर सीधे संबंधित फॉर्म तक पहुंच जाता है। कैटेगरी चुनने के बाद छात्र के सामने एक सीधा–सादा फॉर्म खुलता है, जिसमें नाम, लिंग, पिता का नाम, जन्म तिथि और मोबाइल नंबर जैसी बुनियादी जानकारी भरनी होती है। ईमेल आईडी को वैकल्पिक रखा गया है, ताकि जिन छात्रों के पास ईमेल नहीं है वे भी शिकायत दर्ज करा सकें, जबकि मोबाइल नंबर को ओटीपी से वेरिफाई किया जाता है ताकि हर शिकायत असली छात्र की ओर से ही दर्ज हो।

पोर्टल पर छात्रों के लिए तीन सुविधाएं दी गई हैं। शिकायत दर्ज कराने का विकल्प हॉस्टल सुविधाओं, भोजन, स्वच्छता, सुरक्षा और बिजली से जुड़ी समस्याओं के लिए है। इसके अलावा छात्र व्यवस्था सुधारने से जुड़े अपने सुझाव भी साझा कर सकते हैं, और सबसे अहम बात यह कि एक बार शिकायत दर्ज करने के बाद छात्र उसकी मौजूदा स्थिति और उस पर हुई कार्रवाई को ट्रैक भी कर सकता है। पोर्टल पर सबसे ज्यादा दर्ज होने वाली शिकायतों को भोजन, पेयजल, बिजली, शौचालय–सफाई, सुरक्षा, बुनियादी ढांचे और इंटरनेट जैसी कैटेगरी में पहले से बांटा गया है, जिससे शिकायत सीधे संबंधित विभाग तक पहुंचती है और निपटारे में देरी नहीं होती।

पोर्टल पर दर्ज हर शिकायत का 30 दिनों के भीतर निपटारा सुनिश्चित करने की व्यवस्था की गई है। समाधान के बाद संबंधित छात्र को लिखित रूप से इसकी सूचना भी दी जाती है, ताकि यह साफ रहे कि उसकी शिकायत पर वाकई कार्रवाई हुई है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि शिकायतकर्ता छात्र–छात्राओं की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी, जिससे छात्र बिना किसी डर के अपनी बात रख सकें। जिन छात्रों के पास ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने की सुविधा नहीं है, उनके लिए टोल–फ्री हेल्पलाइन नंबर 1100 भी उपलब्ध कराया गया है।

पोर्टल का मकसद छात्रों की शैक्षणिक, परीक्षा, छात्रावास, छात्रवृत्ति और अन्य सस्थागत समस्याओं का पारदर्शी और जवाबदेह तरीके से समाधान करना है।

सरकारी पोर्टल और हेल्पलाइन की घोषणाएं आमतौर पर होती रहती हैं, लेकिन इनमें से ज्यादातर व्यवहार में उतनी असरदार साबित नहीं होती। लेकिन बिहार सरकार की अब तक की कोशिशों को देखें तो ऐसा लगता है कि सरकार गंभीरता से छात्रों की समस्याओं को सुनने की ओर अग्रसर है। इस पोर्टल की खासियत है कि इसमें एक जवाबदेही तंत्र भी जोड़ा गया है कृ तय समयसीमा में शिकायत का समाधान न होने पर संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई का भी प्रावधान रखा गया है, जिससे यह सिर्फ कागजी व्यवस्था बनकर नहीं रह जाती।

पोर्टल के साथ–साथ सरकार ने हर महीने सहयोग शिविर आयोजित करने की व्यवस्था भी बनाई है, जिनमें मंत्री, विधायक, सासद और संबंधित अधिकारी सीधे स्कूल–कॉलेजों में जाकर छात्रों से बातचीत करेंगे। इन शिविरों में मिलने वाली शिकायतों और सुझावों को भी उसी पोर्टल पर दर्ज कर ट्रैक किया जाता है, जिससे पूरा सिस्टम एक जगह जुड़ा रहता है। यह व्यवस्था खासकर उन इलाकों में उपयोगी मानी जा रही है, जहां छात्र ऑनलाइन माध्यम के बजाय सीधी बात चीत में ज्यादा सहज महसूस करते हैं।

जिन राज्यों में छात्र आंदोलन और कैंपस में अस्तोष की घटनाए सामने आती रही है, उनके लिए बिहार का यह मॉडल कुछ स्पष्ट संकेत देता है। शिकायत निवारण तंत्र तभी प्रभावी होता है जब उसमें तय समयसीमा और जवाबदेही दोनों शामिल हों। शिकायत और छात्रावास की समस्याओं को अलग–अलग कैटेगरी में बांटने और फॉर्म को आसान रखने से समाधान की रफ्तार तेज होती है, जबकि स्टेटस ट्रैक करने की सुविधा से छात्रों को भरोसा रहता है कि उनकी बात पर वाकई काम हो रहा है। साथ ही, सिर्फ डिजिटल पोर्टल पर निर्भर रहने के बजाय हेल्पलाइन और जमीनी शिविर जैसे विकल्प भी जरूरी है, ताकि हर वर्ग का छात्र इस व्यवस्था से जुड़ सके।

शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए बड़ी घोषणाओं के साथ–साथ जमीनी क्रियान्वयन भी उतना ही जरूरी है। बिहार का अनुभव यह दिखाता है कि अगर शिकायत निवारण तंत्र में पारदर्शिता, आसान प्रोसेस और जवाबदेही तय की जाए, तो नतीजे भी सामने आते हैं। अब देखना यह होगा कि अन्य राज्य इस मॉडल से कितना सीखते हैं और अपने यहां इसे किस रूप में लागू करते हैं।

Created by Universal Document Converter

जे.के.एन.सी. महिला विंग द्वारा आयोजित किया गया भव्य सम्मेलन

प्रभा देवी को सर्वसम्मति से जिला अध्यक्ष किया गया नियुक्त

उधमपुर, 31 अगस्त (संजीव शर्मा)। जम्मू कश्मीर नेशनल कांफ्रेंस महिला विंग ने सोमवार को जिला पार्टी कार्यालय में जिला अध्यक्ष सुनील वर्मा की देखरेख में एक भव्य सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें सैकड़ों महिलाओं ने हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में जेकेएनसी की राज्य उपाध्यक्ष और पूर्व विधायक बिमला लूथरा मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुईं। साथ ही महिला विंग की प्रांतीय कार्यकारी अध्यक्ष रजनी देवी भी मौजूद थीं।

सम्मेलन के दौरान, प्रभा देवी को सर्वसम्मति से उधमपुर महिला विंग का जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया। पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने इस फैसले का उत्साहपूर्वक स्वागत किया।

अपने संबोधन में, बिमला लूथरा ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की सोच और जन–केंद्रित नीतियों को हर घर तक पहुंचाने की जरूरत पर जोर दिया और कहा कि सरकार ने महिला सशक्तिकरण और कल्याण को प्राथमिकता दी है। वहीं रजनी देवी ने महिलाओं से एकजुट होने और पूरे जम्मू क्षेत्र में संगठन को मजबूत करने का आह्वान किया।

पार्टी प्रवक्ता आकाश वर्मा ने महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा, शादी के लिए मिलने वाली सहायता राशि को 50,000 से बढ़ाकर 75,000 करना और पात्र एएवाई परिवारों को मुफ्त एलपीजी सिलेंडर देने जैसे अहम कल्याणकारी उपायों का जिक्र किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि वे यह सुनिश्चित करें कि ये लाभ हर जरूरतमंद परिवार तक पहुँचें।

जिला अध्यक्ष सुनील वर्मा ने महिलाओं को सार्थक प्रतिनिधित्व और नेतृत्व के अवसर देकर पार्टी के इरादों को हकीकत में बदलने की प्रतिबद्धता दोहराई।

इस मौके पर सुनीता मेहरा को उधमपुर का शहरी प्रधान, राधे रानी को शहरी उपाध्यक्ष, अनीता देवी को जिला उपाध्यक्ष और एडवोकेट शबनम अख्तर को एसटी विंग का जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया।

डॉ. जितेंद्र पराशर, ब्लॉक अध्यक्ष शंकर सिंह, ओम प्रकाश, तीरथ सिंह, भूपेंद्र अंताल, राम लाल और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने नए पदाधिकारियों को फूलों की माला पहनाकर बधाई दी और शुभकामनाएं दीं। कार्यक्रम का समापन जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करने और लोगों के कल्याण के लिए काम जारी रखने के सामूहिक संकल्प के साथ हुआ।

जम्मू–कश्मीर पीडब्लूडी एम्प्लॉइज वर्कर्स फेडरेशन ने आज सेंट्रल कश्मीर के चीफ इंजीनियर नरिंदर कुमार को उनके रिटायरमेंट के दिन गर्मजोशी से विदाई दी। फेडरेशन के प्रेसिडेंट ने कहा कि वे पूरे जेके में एक बहुत मददगार और भले अधिकारी थे। उन्होंने डिपार्टमेंट के सभी कर्मचारियों की मदद की और खासकर जनता की शिकायतों को कम समय में सुलझाने में हमेशा तत्पर रहे। इस मौके पर जम्मू–कश्मीर पीडब्लूडी एम्प्लॉइज वर्कर्स फेडरेशन के सभी जिलों के प्रेसिडेंट भी मौजूद थे।

छाया: तारिक मीर।

राष्ट्रीय चरित्र के बिना व्यक्तिगत चरित्र अधूरा–अनुराग जी

–बरनोटी में संघ के शताब्दी वर्ष पर प्रमुख जन गोष्ठी, 150 से अधिक प्रबुद्धजनों ने लिया भाग

कठुआ, 31 अगस्त। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में बरनोटी खंड में कमला पैलेस में प्रमुख जन गोष्ठी आयोजित की गई जिसमें 150 से अधिक प्रबुद्धजनों ने भाग लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ भारत माता के चित्र के समक्ष दीप प्रज्ज्वलन से हुआ। मुख्य अतिथि सेवानिवृत्त सीईओ विजय सिंह तथा मुख्य वक्ता संघ के कठुआ विभाग प्रचारक अनुराग जी रहे। खंड संघचालक अंचल जी भी मंच पर उपस्थित रहे।

मुख्य वक्ता अनुराग जी ने 'संघ के 100 वर्षों की यात्रा और आगे की योजना' विषय पर कहा कि राष्ट्रीय चरित्र के बिना व्यक्तिगत चरित्र अधूरा है। डॉ. केशव बलिराम हेडगेवार ने समाज की असंगठित स्थिति को राष्ट्र की कमजोरी का प्रमुख कारण मानते हुए वर्ष 1925 में संघ की स्थापना की और व्यक्ति निर्माण को राष्ट्र निर्माण का आधार बनाया।

उन्होंने कहा कि संघ की

100 वर्षों की यात्रा पांच पीढ़ियों के त्याग, तपस्या और समर्पण से आगे बढ़ी है। उन्होंने समाज की सज्जन शक्ति से राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान करते हुए कुटुंब प्रबोधन, सामाजिक समरसता, पर्यावरण संरक्षण, स्वदेशी और नागरिक कर्तव्य को पंच परिवर्तन के रूप में अपनाने का संदेश दिया। मुख्य अतिथि विजय सिंह ने संघ के समाज को संगठित, जागृत और राष्ट्र के प्रति समर्पित बनाने के प्रयासों की सराहना की। कार्यक्रम का समापन सामूहिक वंदे मातरम् के उद्घोष के साथ हुआ।

महापुरुषों पर श्रद्धा नहीं तो ज्ञान व कल्याण की प्राप्ति भी नहीं: संत सुभाष शास्त्री

उधमपुर, 31 अगस्त (संजीव शर्मा)। चनैनी के गीता भवन में सोमवार से श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम 6 सितम्बर 2026 तक चलेगा। इस अवसर पर डुग्गर प्रदेश के संत सुभाष शास्त्री जी महाराज का भव्य स्वागत किया गया और शोभायात्रा के रुप में गीता भवन लाया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य जजमान आयोजक संयोजक पंडित जगदीश राज शर्मा ने परिवार सहित पूज्य महाराज श्री जी का व्यास पूजन करके उनसे आशीर्वाद लिया।

पूज्य महाराज ने भागवत कथा का श्री गणेश करते हुए संत सुभाष शास्त्री जी महाराज ने सत्संग में श्रद्धालुओं को बताया कि संसार में तीन चीज दुर्लभ हैं–मनुष्यत्वं, मुमुक्षुत्वं, महापुरुष संश्रयः अर्थात मनुष्य का जन्म, मोक्ष की इच्छा महापुरुषों का सत्संग मिलना।

मनुष्यत्वं – मनुष्य शरीर परमात्मा की कृपा से आपको

मिल ही गया है, इसलिए भाग्यशाली हो, क्योंकि देवता भी इस मानव देह की इच्छा करते हैं।

मुमुक्षत्वं– मोक्ष की इच्छा मनुष्य होने पर भी मोक्ष की इच्छा दुर्लभ है। भोग की इच्छा तो बहुतों को होती है। लेकिन मोक्ष की इच्छा सबको नहीं होती। पैसा कमाने की इच्छा होती है, कोठि–कार, बंगले की इच्छा होती है। नेता– अभिनेता आदि बनने की इच्छा होती है। विवाह की, संतान की इच्छा होती है परंतु भगवान की, कल्याण की प्राप्ति की इच्छा कम लोगों को होती है।

शास्त्री जी ने कहा कि वर्तमान समय में व्यक्ति परमात्मा से भी अधिक महत्व पैसे को देता है। पैसा बहुत कुछ है पर सब कुछ पैसा नहीं। पैसे से अधिक महत्व वस्तु का है, क्योंकि वस्तु के लिए हम पैसा दे देते हैं, वस्तु से भी अधिक महत्व व्यक्ति का है, यदि व्यक्ति ही नहीं तो वस्तु किसके लिए, और व्यक्ति का भी महत्व आत्मा को (सत्य को) जान लेने पर है।

संत जी आगे बोले कि मनुष्यत्वं व मुमुक्षत्वं यह दो चीजें प्राप्त हो भी जाएं, तो तीसरी महापुरुष संश्रयः ज्ञानी पुरुष का मिलना दुर्लभ है। ज्ञानी पुरुष को ही महापुरुष कहते हैं। मोक्ष की इच्छा हो और ज्ञानी गुरु ना मिले, दुकानदार मिले ठग गुरु मिले, तो मोक्ष की इच्छा होते हुए भी आप सत्य को (ब्रह्म को) नहीं पा सकते।

भगवान सब जगह पर मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा। ईश्वर प्राप्ति या मुक्ति की इच्छा ही नहीं तो बात बनेगी नहीं। महापुरुषों पर श्रद्धा नहीं तो ज्ञान व कल्याण की प्राप्ति भी नहीं। गीता में कहा है कि जितेंद्रय, साधन परायण और श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है तथा ज्ञान को प्राप्त होकर वह बिना विलंब के तत्काल ही भगवत प्राप्ति, परम शांति को प्राप्त हो जाता है।

पीहू गुप्ता ने लुधियाना में आयोजित मॉडलिंग प्रतियोगिता में जीता प्रथम पुरस्कार

उधमपुर, 31 अगस्त (संजीव शर्मा)। लुधियाना में आयोजित मॉडलिंग प्रतियोगिता में पीहू गुप्ता पुत्री अरुण कुमार निवासी उधमपुर ने 9 से 14 आयु वर्ग में प्रथम पुरस्कार जीत कर उधमपुर जिले, अपने माता–पिता का नाम रोशन किया है।

नीट में शानदार सफलता पर टाइनी स्कॉलर्स स्कूल ने किया मेधावी विद्यार्थियों का सम्मान

कठुआ, 31 अगस्त। टाइनी स्कॉलर्स स्कूल ने नीट परीक्षा में शानदार प्रदर्शन कर प्रतिष्ठित सरकारी मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश हासिल करने वाले अपने मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया। विद्यार्थियों की इस उपलब्धि से उनके अभिभावकों, शिक्षकों और पूरे स्कूल परिवार में खुशी का माहौल है।

सम्मान समारोह के दौरान विद्यार्थियों की मेहनत, लगन, दृढ़ संकल्प और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पण की सराहना की गई। स्कूल प्रबंधन ने कहा कि विद्यार्थियों की यह सफलता विद्यालय में दी जा रही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, शिक्षकों के मार्गदर्शन और अभिभावकों के निरंतर सहयोग का परिणाम है। स्कूल की प्रधानाचार्य पूजा गुप्ता ने बधाई देते हुए कहा कि टाइनी स्कॉलर्स स्कूल की कक्षाओं से निकलकर सरकारी मेडिकल कॉलेजों तक पहुंचना अन्य विद्यार्थियों के लिए भी प्रेरणादायक है। उन्होंने विद्यार्थियों की मेहनत के साथ–साथ शिक्षकों के मार्गदर्शन और अभिभावकों के

सहयोग की भी सराहना की। वही स्कूल की प्रबंध निदेशक मनीषा गुप्ता ने सभी सफल विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। उन्होंने उम्मीद जताई कि विद्यार्थी भविष्य में चिकित्सा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए समाज की सेवा करेंगे। इस अवसर पर विद्यार्थियों को चिकित्सा क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए करुणा, ईमानदारी, सेवा भावना और उत्कृष्टता के मूल्यों को अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। स्कूल प्रबंधन ने कहा कि विद्यार्थियों की यह उपलब्धि टाइनी स्कॉलर्स स्कूल की युवा प्रतिभाओं को उनके सपनों को साकार करने के लिए सशक्त बनाने की प्रतिबद्धता को और मजबूत करती है।

मासिक प्रशिक्षण भत्ता बढ़ाने की मांग को लेकर एमबीबीएस इंटर्न्स का हल्ला बोल, 12 हजार से बढ़ाकर 30 हजार रुपये करने की मांग

कठुआ, 31 अगस्त। मासिक प्रशिक्षण भत्ता बढ़ाने की मांग को लेकर राजकीय मेडिकल कॉलेज कठुआ के एमबीबीएस इंटर्न्स ने सोमवार को परिसर में प्रदर्शन कर अपनी मांग को लेकर आवाज बुलंद की। इंटर्न्स ने वर्तमान में मिल रहे करीब 12 हजार रुपये प्रशिक्षण भत्ते को बढ़ाकर कम से कम 30 हजार रुपये किए जाने की मांग की।

प्रदर्शनकारी इंटर्न्स ने कहा कि अस्पताल में किसी भी मरीज के इमरजेंसी में पहुंचने पर सबसे पहले मरीजों का सामना और प्रारंभिक स्तर पर देखभाल करने वालों में इंटर्न्स शामिल होते हैं। ऑपरेशन थिएटर, वार्ड और इमरजेंसी सहित विभिन्न विभागों में वे कई बार 12 से 24 घंटे तक ड्यूटी निभा रहे हैं। इसके बावजूद उन्हें मिलने वाला भत्ता वर्तमान महंगाई के हिसाब से बेहद कम है। इंटर्न्स ने बताया कि भत्ता बढ़ाने की मांग वे पिछले कई वर्षों से उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हाल ही में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री सकीना इट्टू के समक्ष भी यह मुद्दा रखा गया था। मंत्री की ओर से बताया गया था कि

संबंधित फाइल वित्त विभाग के पास है, लेकिन इंटर्न्स का आरोप है कि पिछले करीब तीन वर्षों से वित्त विभाग की ओर से इस मामले में कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया।

इंटर्न्स ने कहा कि प्रशिक्षण भत्ता में बढ़ोतरी की मांग को लेकर जम्मू–कश्मीर के विभिन्न जीएमसी में भी इंटर्न्स प्रदर्शन और हड़ताल कर रहे हैं। उन्होंने सरकार से मांग की कि बढ़ती महंगाई और उनकी कार्य जिम्मेदारियों को देखते हुए मासिक प्रशिक्षण भत्ता को तत्काल बढ़ाकर 30 हजार रुपये किया जाए।

प्रदर्शनकारियों ने कहा कि एमबीबीएस इंटर्न्स अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाओं का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और मरीजों की सेवा में लंबे समय तक ड्यूटी देने के बावजूद उन्हें पर्याप्त आर्थिक सहायता नहीं मिल रही है। उन्होंने सरकार से मामले में शीघ्र हस्तक्षेप कर उनकी मांग को पूरा करने की अपील की।

सनातन धर्म सभा की ओर से श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य पर 03 सितम्बर 2026 को निकाली जाएगी शोभायात्रा

शोभायात्रा को लेकर सनातन धर्म सभा ने की बैठक

उधमपुर, 31 अगस्त (संजीव शर्मा)। सनातन धर्म सभा उधमपुर हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य पर शोभायात्रा का कार्यक्रम गुरुवार 03 सितम्बर 2026 को आयोजित करने जा रही है। इस संदर्भ में आयोजन समिति की एक बैठक सोमवार को सनातन धर्म सभा कार्यालय में प्रधान विक्रमादित्य गुप्ता की अध्यक्षता में हुई। जिसमें इस वर्ष निकाली जाने वाली भव्य शोभा यात्रा को लेकर किए जाने वाले प्रबंधों को लेकर चर्चा की गई। इसके उपरांत इस पूरे कार्यक्रम की जानकारी प्रेस वार्ता के जरिए प्रधान विक्रमादित्य गुप्ता द्वारा दी गई।

उन्होंने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी विभिन्न धार्मिक, सामाजिक और शैक्षिक संस्थाओं की झाकियां सनातन धर्म सभा उधमपुर के कार्यालय के बाहर 3 बजे 03 सितम्बर

2026 को एकत्रित होंगी। ठीक चार बजे विभिन्न झांकियां जो भगवान श्रीकृष्ण जी के जीवन के चरित्र को दर्शा रही होंगी, मेन बाजार, गोल मार्केट, मुखर्जी बाजार, रामनगर चौक, कोर्ट रोड, सलाथिया चौक, फिर वापस कोर्ट रोड से रामनगर चौक, अस्पताल रोड से होते हुए सैला तालाब में संपन्न होंगी।

इस अवसर पर बताया गया कि इस शोभा यात्रा में विभिन्न संस्थाओं की झांकियां जिनमें राम कला केन्द्र चबूतरा बाजार, बाल युवा श्री राम कला केंद्र शीतला माता गली, हरे राम हरे कृष्णा इस्कॉन, ब्रह्मर्षि बावरा शांति विद्या पीठ, जे.के. पब्लिक स्कूल, भारतीय विद्या मंदिर स्कूल, कॉमन पब्लिक स्कूल, एवरग्रीन पब्लिक स्कूल नगरोटा, विजय हायर सेकेंडरी स्कूल, इंदिरा अकादमी, आर्य समाज हाई स्कूल, सनरेज पब्लिक स्कूल, महाराजा हरि सिंह डीएवी पब्लिक स्कूल, हैप्पी मॉडल स्कूल, सैनफोर्ट अकादमी की झांकियां इसमें सम्मिलित होने की संभावना है।

इस अवसर पर उन्होंने उधमपुर और आसपास के सभी श्रद्धालुओं से निवेदन किया कि वे सभी इस कार्यक्रम में बढ़–चढ़कर के भाग लें और भगवान श्रीकृष्ण जी का आशीर्वाद प्राप्त करें।

इस अवसर पत्रकार वार्ता में डॉ.जोगेश्वर गुप्ता, बृज रैणा, विक्रम सिंह सलाथिया, अजय गुड्डा, रवि गुड्डा, उमेश शर्मा, महेंद्र सिंह, जय कृष्ण गुप्ता आदि मौजूद रहे।

चंदे में पारदर्शिता की मांग को लेकर ऊधमपुर में कांग्रेस की चौपाल, निष्पक्ष जांच की उठी मांग

उधमपुर, 31 अगस्त (संजीव शर्मा)। चंदे में कथित अनियमितताओं और पारदर्शिता की मांग को लेकर सोमवार को ऊधमपुर ब्लॉक हेड क्वार्टर, सलाथिया चौक में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा चौपाल कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष रामपाल भगत ने की, जबकि जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुमित मगोत्रा विशेष रूप से उपस्थित रहे।

इस अवसर पर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष रामपाल भगत ने कहा कि देश के करोड़ों श्रद्धालुओं ने अपनी आस्था और श्रद्धा के साथ राम मंदिर के लिए योगदान दिया है। ऐसे में चंदे से जुड़े किसी भी सवाल को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि जनता के मन में उठ रहे सवालों का जवाब पारदर्शी तरीके से मिलना चाहिए और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच

होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आस्था के नाम पर किसी भी प्रकार की अनियमितता स्वीकार नहीं की जा सकती।

जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुमित मगोत्रा ने कहा कि कांग्रेस किसी की आस्था का विरोध नहीं करती, बल्कि जनता के विश्वास और मेहनत की कमाई के सम्मान की बात करती है। उन्होंने कहा कि जब आम लोगों ने श्रद्धा से अपना पैसा योगदान के रूप में दिया है, तो उस पैसे का पूरा और पारदर्शी हिसाब जनता के सामने होना चाहिए।

सुमित मगोत्रा ने कहा, कि हम किसी व्यक्ति को बिना जांच दोषी नहीं ठहरा रहे, लेकिन अगर चंदे को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं तो निष्पक्ष जांच क्यों नहीं होनी चाहिए, सच्चाई सामने आनी चाहिए और अगर किसी स्तर पर गड़बड़ी पाई जाती है तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस की मांग बिल्कुल स्पष्ट है–चंदे से जुड़े पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो, वित्तीय रिकॉर्ड सार्वजनिक किए जाएं और जनता को सच्चाई बताई जाए। उन्होंने कहा कि यह मामला केवल राजनीतिक बहस का नहींए बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं के विश्वास और जनता की भावनाओं से जुड़ा हुआ है। इस मौके पर जिला कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अनिल पचियाला, गुंजार सिंह, शशि मन्हास, हंस राज ठाकुर, मनमोहन रैना, सतीश खजूरिया, अशोक जंडियाल, मनजीत भगत, विनोद डोगरा, शाम लाल, अरविंद खजूरिया, विकास, राजेश, मुकेश भारती, शिवम, भानु प्रताप और सुरेंद्र केसरी सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे।

Created by Universal Document Converter

नेपाल में भीषण बाढ़ से भारी तबाही, 939 लोगों की मौत और करीब 4 हजार लापता

काठमांडू। नेपाल में अचानक आई भीषण बाढ़ के कारण मरने वालों की संख्या सोमवार को बढ़कर 939 हो गई जबकि करीब 4,000 लोग अब भी लापता हैं। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अब तक 10,000 से अधिक लोगों को बचाया जा चुका है और बचाव दल रुक–रुक कर हो रही बारिश, उफनती नदियों, क्षतिग्रस्त सड़कों व पुलों के बीच फंसे लोगों तक पहुंचने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

नेपाल–तिब्बत सीमा के पास बर्फ और चट्टानों के टूटने के कारण 26 अगस्त को आई बाढ़ ने उत्तरी और मध्य नेपाल के कस्बों और गांवों को तबाह कर दिया था। हिमालयी सीमा क्षेत्र से दक्षिण की ओर बहने वाली भोटेकोशी नदी बाढ़ के पानी को अपने साथ नीचे की ओर ले गई, जिससे घर, वाहन, सड़कें और पुल बह गए तथा जलविद्युत परियोजनाओं को नुकसान पहुंचा। इस आपदा में चीनी क्षेत्र में भी 16 लोगों की मौत हुई है जबकि चीनी मीडिया में आई खबरों के अनुसार तिब्बत में करीब 550 लोग अब भी लापता हैं।

अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि बचाव दल नेपाल के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में विभिन्न जलविद्युत परियोजना स्थलों पर 639 श्रमिकों और कर्मचारियों का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इनमें से कई लोगों के सुरंगों में फंसे होने की आशंका है। एक स्थान पर बचाव दलों को बंद सुरंग तक पहुंचने में परेशानी हुई, जिसके बाद नियंत्रित विस्फोट किया गया।

इन अभियानों में भारत और चीन की विशेषज्ञ टीमें बचाव दलों की सहायता कर रही हैं। नेपाल ने सुरंगों में बचाव कार्य और फोरेंसिक जांच के लिए विशेष उपकरणों व तकनीकी

सहायता समेत अतिरिक्त अंत. रराष्ट्रीय मदद मांगी है। नेपाल के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लोक बहादुर छेत्री ने सोमवार को संवाददाता सम्मेलन में कहा कि देश ने अमेरिका से फ्रीजर, डीएनए जांच किट और लाइडार जैसी जरूरी गैर–खाद्य सामग्री और सेवाएं मांगी हैं।

इसके अलावा सिंगापुर से आपदा पीड़ितों की पहचान (डीवीआई) से जुड़ी सामग्री और चीन व सिंगापुर से बेल्ली पुल तथा अधिक क्षमता वाले ड्रोन मांगे गए हैं। अब तक नेपाल को शवों के प्रबंधन के लिए एयर टाइट बैग मिले हैं, जबकि और बैग भी भेजे जा रहे हैं। डीएनए विश्लेषण में विशेषज्ञता रखने वाले भारत के 18 फोरेंसिक विशेषज्ञों का दल शनिवार से नेपाल में मौजूद है और अधिकारियों की मदद कर रहा है।

राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीआरआरएमए) ने सोमवार को बताया कि नेपाल के चितवन जिले में 279, नवलपरासी पूर्व में 216, नवल. परासी पश्चिम में 168, नुवाकोट में 95, गोरखा में 65, धादिंग में 55, तनहूं में 38 और रसुवा में 23 शव बरामद किए गए हैं। नेपाल के अस्पतालों में अपने लापता रिश्तेदारों की तलाश करने वाले लोगों की भीड़ उमड़ रही है। अब ध्यान तेजी से मृतकों की पहचान करने पर केंद्रित हो गया है।

अस्पतालों की दीवारों के बाहर तस्वीरें चिपकाई गई हैं, जहां बड़ी संख्या में लोग उन्हें देखकर अपने परिजन को पहच. ानने की कोशिश कर रहे हैं। सोमवार तक बरामद सैकड़ों शवों में से केवल कुछ दर्जन शवों की ही पहचान हो पाई थी। अधिकारियों ने कहा कि कई शव लंबे समय तक बाढ़ के पानी में रहने के कारण बुरी तरह क्षत–विक्षत हैं और उन्हें पहचानना मुश्किल है।

अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि नेपाल में अब भी लापता 3,925 लोगों में से कम से कम 39 देशों के 590 विद. ेशी नागरिक शामिल हैं, जिनम. े भारत के लोग भी हैं। इनमें 83 सुरक्षाकर्मी भी शामिल हैं। नयी दिल्ली में विदेश मंत्रालय (एमईए) ने शनिवार को कहा था कि नेपाल में 275 से अधिक भारतीय और भारतीय मूल के 128 लोग अब भी लापता हैं और उनसे संपर्क नहीं हो पाया है।

नीट पीजी के बाद अब एम्स के पेपर पर बवाल, 30 मिनट में बंद पड़ीं स्क्रीन्स, अभ्यर्थियों ने जाहिर किया गुस्सा

जयपुर। राजस्थान की राजधानी जयपुर में अभी नीट पीजी के दौरान हुई गड़बड़ी का मामला शांत भी नहीं हुआ था कि एक बार फिर से हंगामा हो गया। बता दें कि 25 जुलाई 2026 को आयोजित हुई मूल परीक्षा में आउट ऑफ सिलेबस सवाल पूछे जाने के विवाद के बाद, परीक्षा एजेंसी ने सोमवार को एम्स सीआरई–5 का री–एग्जाम आयोजित करने का निर्णय लिया था। हालांकि, लेकिन आज हुए एग्जाम में भी अभ्यर्थियों की उम्मीदों पर पानी फिर गया। आज परीक्षा शुरू होने के महज आधे घंटे के भीतर ही सेंटर का सर्वर पूरी तरह ध्वस्त हो गया।

सोमवार सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे की पारी में आयोजित इस परीक्षा के शुरू होते ही कंप्यूटर स्क्रीन अचानक बंद होने लगीं। देखते ही देखते पूरा डिजिटल सिस्टम ठप पड़ गया। दूर–दराज के जिलों से भारी आर्थिक खर्च और मानसिक तनाव झेलकर जयपुर पहुंचे परीक्षार्थियों के सब्र का बांध टूट गया। परीक्षा केंद्र की इस गंभीर लापरवाही से आक्रोशित छात्रों ने सेंटर के अंदर और बाहर जोरदार नारेबाजी शुरू कर दी और परीक्षा को तुरंत रद्द करने की मांग पर अड़ गए।

बटवाल सुधार सभा जम्मू कश्मीर की तरफ से नव नियुक्त सदस्यों को दिए गए नियुक्ति पत्र

आरएस पुरा। बटवाल सुधार सभा जम्मू कश्मीर की तरफ से सोमवार को मीरा साहिब क्षेत्र के गांव चक सिया में कार्यक्रम का आयोजन के सभा के नव नियुक्त सदस्यों को नियुक्ति पत्र दिए गए। बटवाल सुधार सभा जम्मू कश्मीर के चेयरमैन सतपाल मांडी की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान सभा के प्रधान मास्टर अजैब सिंह मोटन, सभा के मुख्य संरक्षक गारा राम मोटन कोषाध्यक्ष श्याम लाल पंडित, मुख्य सलाहक. ार रिटायर्ड सीएमओ गिरधारी लाल मोटन, उप चेयरमैन कृपाल संधू सहित सभा के अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे जिन्हें प्रधान एवं चेयरमैन की मौजूदगी में नियुक्ति पत्र दिए गए। कार्यक्रम के दौरान अन्य बिरादरी के लोग भी उपस्थित रहे जिन्होंने सभा के सदस्यों को सम्मानित किया और विश्वास दिलाया कि सभी बिरादरी के लोग एकजुट होकर समाज की भलाई एवं बेहतरी के लिए कार्य करेंगे। इस मौके पर बटवाल सुधार सभा

जम्मू कश्मीर के प्रधान मास्टर अजैब सिंह मोटन तथा चेयरमैन सतपाल मांडी ने कहा कि कुछ दिन पहले बटवाल सुधार सभा का कुछ बदलावों के साथ गठन किया गया था और आज सभी सदस्यों को सभा की तरफ से नियुक्ति पत्र देने के साथ–साथ उन्हें बिरादरी तथा समाज की बेहतरी हेतु किए जाने वाले कार्यो के लिए जिम्मेदारी भी दी गई है। उन्होंने बताया कि आज इस कार्यक्रम में बटवाल सभा के साथ–साथ अन्य बिरादरियों के लोग भी मौजूद रहे जिन्होंने फैसला लिया कि सभी लोग समाज को नई दिशा की तरफ ले जाने में एकजुट होकर कार्य करेंगे। इस मौके पर सभा के मुख्य संरक्षक गारा राम मोटन ने कार्यक्रम में शामिल हुए सभी लोगों का स्वागत किया और कहा कि सभा का प्रयास रहेगा की बटवाल बिरादरी के साथ–साथ समाज को भी एकजुट किया जाए और खासकर नौजवान पीढ़ी को नशा जैसी पूरी आदतों से दूर रखा जाए। इस मौके पर उप चेयरमैन वेद प्रकाश, नंबरदार सेवाराम, सरदार बलबीर सिंह, पूर्व पंच बिशन दास भगत, पूर्व पंच हंसराज भगत, पूर्व पंच सत्या देवी, जनक राज, राजेंद्र कुमार अंगुराना, सरदार हरमीत सिंह, मोहन सिंह, पूर्व नायब सरपंच सोमनाथ, पूर्व नगर अध्यक्ष बड़ी ब्राह्मणा कैप्टन बचन लाल, ओम प्रकाश मोटन, तहसील प्रधान अशोक सिंह, नरेश मांडी, रामधन थापा तथा जनक राज मांडी सहित बड़ी संख्या में सभा के सदस्य एवं अलग–अलग संगठनों से जुड़े हुए लोग मौजूद रहे।

पीएम मोदी ने किर्गिस्तान में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी

बिश्केक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन के लिए किर्गिस्तान की अपनी यात्रा के दौरान यहां महात्मा गांधी के स्मारक पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने बिश्केक में अलग–अलग समुदायों के लोगों से भी मुलाकात की।

प्रधानमंत्री रविवार को 26वें एससीओ लीडरशिप समिट में शामिल होने और सदस्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करने के लिए बिश्केक पहुंचे। एयरपोर्ट पर किर्गिज़ गणराज्य के कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स के चेयरमैन अडिलबेक कासिमालीव ने उनका स्वागत किया। उनके स्वागत में पारंपरिक किर्गिज़ नृत्य का प्रदर्शन भी किया गया।

होटल में वंदे मातरम के नारों के साथ मोदी का स्वागत किया गया, जहां उन्होंने देशभक्ति गीत मां तुझे सलाम पर योग प्रदर्शन और भगवान शिव पर आधारित सांस्कृतिक नृत्य भी देखा। मोदी राष्ट्रपति सादिर झापारोव के निमंत्रण पर 31 अगस्त–1 सितंबर को होने वाले एससीओ शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए किर्गिस्तान की यात्रा कर रहे हैं।

10 सदस्यों वाला एससीओ इस साल अपनी स्थापना की 25वीं वर्षगांठ मना रहा है। इस समूह की स्थापना 2001 में चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान ने की थी।

भारत और पाकिस्तान 2017 में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल हुए, इसके बाद 2023 में ईरान और 2024 में बेलारूस शामिल हुए।

शनिवार को रवानगी से पहले अपने बयान में मोदी ने कहा कि वह ष्सुरक्षा, कनेक्टिविटी और अवसर पर आधारित इस क्षेत्र के लिए भारत के विजन को आगे बढ़ाने और ष्आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवादष से मुक्त क्षेत्र के लिए एससीओ के साथी सदस्यों के साथ काम करने के लिए उत्सुक हैं।

उज्बेकिस्तान की दो दिवसीय यात्रा के बाद मोदी बिश्केक पहुंचे; इस यात्रा के दौरान दोनों देशों ने अपने संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने और 2030 तक सालाना 5 अरब अमेरिकी डॉलर के व्यापार का लक्ष्य तय करने का फैसला किया।

अशोक कुमार बने आरएस पुरा जम्मू दक्षिण जोन से पीडीपी के जोन प्रधान

पंचायती एवं निकाय चुनाव को लेकर पीडीपी पूरी तरह से तैयारः नरेंद्र शर्मा

आरएस पुरा। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की तरफ से सोमवार को गांव कोटली शाह दुल्ला में कार्यक्रम का आयोजन कर आर एस पुरा–जम्मू दक्षिण विधानसभा क्षेत्र की जोन इकाई का गठन किया गया। पीडीपी के वरिष्ठ नेता तथा विधानसभा प्रभारी नरेंद्र शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक के दौरान पार्टी के प्रदेश महासचिव एवं पार्टी द्वारा नियुक्त किए गए रिटर्निंग ऑफिसर सतपाल चाढक के साथ–साथ चुनाव आब्जर्वर सुखविंदर सिंह, पार्टी के वरिष्ठ नेता वरिंदर सिंह सोनू, विक्की कुमार डोगरा सहित पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद रहे जिनकी मौजूदगी में सर्व सहमति के साथ अशोक कुमार को आरएस पुरा जम्मू दक्षिण जोन से पार्टी का जोन अध्यक्ष बनाया गया। इसके अलावा रवि भगत तथा सुदेश कुमार को उप प्रधान, साहिल कुमार को सचिव, चरण सिंह को ऑर्गेनाइजर सेक्रेटरी, सनी सोढ़ी को प्रचार सचिव तथा अंकित शर्मा को जोन का

कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया। इसके अलावा कार्यकारिणी सदस्यों के नाम की घोषणा भी पार्टी की तरफ से की गई। इस मौके पर सर्व सहमति के साथ चुने गए जोन प्रधान अशोक कुमार तथा उनकी पूरी टीम का पार्टी नेताओं द्वारा हार पहना कर जोरदार तरीके के साथ स्वागत किया गया। इस मौके पर पार्टी महासचिव सतपाल चाढक् ने कहा कि पीडीपी की तरफ से जोन स्तर पर नई इकाइयों का गठन किया जा रहा है और उसी के चलते आज आरएस पुरा जम्मू दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में भी पार्टी की तरफ से नई इकाई का गठन किया गया है जिसमें अशोक कुमार को सर्व सहमति के साथ जोन का प्रधान बनाया गया है। इसके अलावा दो उप प्रधान के साथ–साथ अन्य लोगों को भी पार्टी की तरफ से जिम्मेदारी दी गई है। उन्होंने कहा कि पार्टी की तरफ से गठित की गई कमेटी एक तरफ जहां लोगों की समस्याओं को सुनकर उनका समाधान करने का पूरा प्रयास करेगी वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में होने वाले निकाय एवं पंचायती चुनाव को लेकर भी गठित कमेटी द्वारा सक्रिय रूप के साथ कार्य किया जाएगा। उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों को विश्वास दिलाया कि पीडीपी लोगों से जुड़े हुए मुद्दों को प्रमुखता के सरकार के समक्ष रखने का प्रयास करेगी। इससे पहले पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र शर्मा ने अपने विचार रखे और कहा कि अशोक कुमार तथा उनकी पूरी टीम पिछले लंबे समय से पीडीपी के साथ जुड़ी हुई है और उनके बेहतर कार्य को देखते हुए आज पार्टी की तरफ से उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। इस अवसर पर जोन अध्यक्ष बनाए जाने पर अशोक कुमार ने पार्टी हाई कमान का धन्यवाद किया और कहा कि उनका प्रयास रहेगा की पार्टी की नीतियों को जन–जन तक पहुंचाया जाए। इस मौके पर पार्टी के अन्य लोगों ने भी अपने–अपने विचार रखें।

सरकारी बॉयज मिडिल स्कूल गोपड में चलाया गया पौधारोपण अभियान

आरएस पुरा। सरकारी बॉयज मिडिल स्कूल गोपड में सोमवार को पौधारोपण अभियान चलाया गया और अभियान के तहत स्कूल परिसर में कई फलदार एवं छायादार पौधे लगाए गए। इस मौके पर विधायक प्रोफेसर गारू राम भगत मुख्य तौर पर उपस्थित रहे जिन्होंने स्कूल स्टाफ के सदस्यों, विद्यार्थियों तथा विलेज कमेटी के सदस्यों की मौजूदगी में इस अभियान को चलाया और लोगों से अपील करते हुए कहा कि पर्यावरण को सुरक्षित एवं संतुलित रखने के लिए ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाए। इस मौके पर विधायक ने सरकारी बॉयज मिडिल स्कूल गोपड के विकास के लिए लगभग 3 लाख रूपए की राशि भी मंजूर की और कहा कि जल्द स्कूल के विकास के लिए कार्य शुरू कर दिया जाएगा। इस मौके पर स्कूल के विद्यार्थियों ने जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि वह इन पौधों की पूरी देखभाल करेंगे। वहीं विधायक ने अपने संबोधन में

कहा कि पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने की जरूरत है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी लोगों से अपील की जा रही है कि एक पेड़ मां के नाम के तहत सभी लोग पौधे लगाए। उन्होंने स्कूल परिसर में पौधारोपण अभियान चलाने के लिए स्कूल प्रबंधन तथा विलेज कमेटी के सदस्यों की भी प्रशंसा की और कहा कि ऐसे अभियान भविष्य में भी जारी रहने चाहिए। इस मौके पर जोनल शिक्षा अधिक. ारी आरएस पुरा, स्कूल के हेड मास्टर सुरजीत कुमार, अध्यापक विजय कुमार,दयाराम, संजीव कुमार उषा शर्मा, जसमीत कौर के अलावा स्थानीय निवासी श्याम लाल शर्मा, राम सिंह, श्याम सिंह सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण एवं विद्यार्थियों के अभिभावक मौजूद रहे।

भाजपा ओबीसी मोर्चा उधमपुर ने सुनाड़ी में आयोजित की संगठनात्मक बैठक, पार्टी को मजबूत करने और जमीनी स्तर पर जनसंपर्क की समीक्षा

उधमपुर, 31 अगस्त, 2026। भाजपा ओबीसी मोर्चा, जिला उधमपुर द्वारा सुनाड़ी में एक महत्वपूर्ण संगठनात्मक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक का संयुक्त आयोजन जीब रामबल मंडल और क्रिमची मंडल द्वारा किया गया, जिसका उद्देश्य जमीनी स्तर पर पार्टी संगठन की समीक्षा करना तथा उसे और अधिक मजबूत करना था।

बैठक का आयोजन रवि कुमार अबरोल, प्रभारी, जिला उधमपुर तथा सागर वर्मा, जिला अध्यक्ष, भाजपा ओबीसी मोर्चा, उधमपुर के दिशा–निर्देशों के तहत किया गया।

बैठक में प्रमुख पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष, वरिष्ठ भाजपा नेता, ओबीसी समुदाय के प्रतिनिधि तथा समर्पित पार्टी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस अवसर पर रवि कुमार अबरोल, प्रभारी, जिला उधमपुरय सागर वर्मा, जिला अध्यक्ष, भाजपा ओबीसी मोर्चा, उधमपुरय कुलदीप कुमार प्रजापति, महासचिवय अशोक कुमार बांद्राल, महासचिवय रवि कुमार, मंडल प्रधान, जीब रामबलय राकेश कुमार, मंडल प्रधान, क्रिमचीय भूषण कुमार, मंडल प्रधान, मोंगरीय राज कुमार, मंडल प्रधान, टिकरी मल्हारय तथा सौरव कुमार, मंडल प्रधान, जगानू के अलावा कई वरिष्ठ नेता एवं पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे।

बैठक के दौरान बूथ एवं मंडल स्तर पर संगठन को मजबूत करने, पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं के बीच बेहतर समन्वय बढ़ाने, ओबीसी समुदाय के बीच पार्टी की पहुंच का विस्तार करने तथा केंद्र सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों एवं कल्याणकारी पहलों को जमीनी स्तर तक पहुंचाने को लेकर विस्तृत चर्चा की गई।

वक्ताओं ने जोर देते हुए कहा कि बूथ स्तर पर मजबूत संगठन एक प्रभावी राजनीतिक एवं सामा. जिक जनसंपर्क कार्यक्रम की नींव है। पार्टी कार्यकर्ताओं से आग्रह किया गया कि वे जनता के साथ नियमित संपर्क बनाए रखें, उनकी समस्याओं और चिंताओं को समझें तथा यह सुनिश्चित करें कि पात्र लाभार्थी विभिन्न सरकारी कल्याणकारी एवं विकास योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकें।

प्रतिभागियों ने आगामी संगठनात्मक कार्यक्रमों पर भी चर्चा की तथा जिला उधमपुर में भाजपा ओबीसी मोर्चा को और मजबूत करने के लिए रणनीतियां तैयार कीं। कार्यकर्ताओं के बीच एकता, अनुशासन और समन्वय बनाए रखने पर विशेष जोर दिया गया, ताकि जनसेवा एवं समावेशी विकास के व्यापक उद्देश्य को आगे बढ़ाया जा सके।

सभा को संबोधित करते हुए रवि कुमार अबरोल, प्रभारी, जिला उधमपुर ने कहा कि संगठनात्मक बैठकें जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं तथा संगठन की प्रगति की समीक्षा करने और उन क्षेत्रों

की पहचान करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करती हैं, जहां अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।

उन्होंने कहा कि भाजपा ओबीसी मोर्चा को ओबीसी समुदाय के कल्याण के लिए समर्पण, एकता और प्रतिबद्धता के साथ लगातार कार्य करते रहना चाहिए तथा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सरकारी कल्याणकारी एवं विकास योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र एवं जरूरतमंद परिवार तक पहुंचे।

अबरोल ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में देश ने अभूतपूर्व विकास, सामाजिक सशक्तिकरण और समावेशी विकास देखा है, जिसम. े ओबीसी समुदाय सहित समाज के कमजोर एवं वंचित वर्गों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से जनसेवा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता बनाए रखने, बूथ स्तर पर संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने तथा सरकार की उपलब्धियों एवं जनकल्याणकारी नीतियों को प्रत्येक घर तक पहुंच. ाने का आह्वान किया।

ब्रह्म ज्योत सत्ती, वरिष्ठ भाजपा नेता एवं प्रदेश अध्यक्ष, भाजपा ओबीसी मोर्चा, जम्मू–कश्मीर, ने अपने संदेश में जिला उधमपुर इकाई द्वारा बैठक आयोजित करने के प्रयासों की सराहना की और जमीनी स्तर पर निरंतर जनसंपर्क की आवश्यकता पर जोर दिया।

उन्होंने कहा कि भाजपा की ताकत उसके समर्पित कार्यकर्ता और जनता के साथ उसका सीधा जुड़ाव है। उन्होंने ओबीसी मोर्चा के कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे सरकार और समुदाय के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करें, लोगों की वास्तविक समस्याओं की पहचान करें और उन्हें उनके कल्याण के लिए शुरू की गई विभिन्न योजनाओं एवं पहलों के बारे में जागरूक करें।

उन्होंने जोर देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ओबीसी समुदाय ने महत्वपूर्ण प्रगति की है, जिसमें सामाजिक न्याय, राजनीतिक भागीदारी, शिक्षा, रोजगार, उद्यमिता तथा कमजोर वर्गों के सशक्तिकरण पर विशेष जोर दिया गया है।

उन्होंने कार्यकर्ताओं से प्रत्येक मंडल एवं बूथ में संगठन को मजबूत करने, ओबीसी समुदाय के सदस्यों की पार्टी गतिविधियों में अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने तथा "सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास" के संदेश को जमीनी स्तर तक पहुंच. ाने का आह्वान किया।

उन्होंने मंडल स्तर के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया और कहा कि नियमित बैठकें, जनसंपर्क कार्यक्रम तथा समाज के साथ रचनात्मक संवाद एक मजबूत एवं अधिक उत्तरदायी संगठन के निर्माण के लिए आवश्यक है।

बैठक का समापन पदाधिकारियों एवं पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा जिला उधमपुर में भाजपा ओबीसी मोर्चा को मजबूत करने, जमीनी स्तर पर संगठन की उपस्थिति का विस्तार करने तथा समाज के प्रत्येक वर्ग के कल्याण एवं सशक्तिकरण के लिए सामूहिक रूप से कार्य करने की प्रतिबद्धता के साथ हुआ।

Created by Universal Document Converter

सप्तधारा बनाएगी विकसित भारत

अनिल बलूनी

भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस के ऐतिहासिक अवसर पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 2047 तक श्विकसित भारतश् के निर्माण का एक स्पष्ट, पारदर्शी और दूरगामी खाका देश के सामने रखा। स्वतंत्रता दिवस समारोह के इतिहास में पहली बार संपूर्ण श्वंदे मातरम्श् के गायन के साथ राष्ट्र ने अपनी क्षमताओं को सुदृढ़ करने का नया संकल्प लिया। 2022 के श्पंच प्रणश् से आगे बढ़ते हुए अब देश श्सप्तधाराश् (सामर्थ्य की सात धारा) के मार्ग पर आगे बढ़ चुका है, जो भारत की आर्थिक, तकनीकी और रणनीतिक क्षमता को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। श्सप्तधाराश् केवल सरकारी नीतियों का पुलिंदा नहीं है, बल्कि यह 140 करोड़ भारतीयों के सामूहिक सपनों का प्रकटीकरण है। विकास की सप्तधारा के सात प्रमुख स्तंभ नए भारत की नींव रख रहे हैं।

इनमें पहला है विनिर्माणरू श्मेक इन इंडियाश, श्स्वदेशीश और श्वोकल फार लोकलश के मंत्र ने जमीनी स्तर पर क्रांति ला दी है। 2014–15 में हमारा इलेक्ट्रानिक उत्पादन लगभग 1.9 लाख करोड़ रुपये था, जो 2024–25 में करीब छह गुना बढ़कर 12 लाख करोड़ रुपये हो गया। इसी तरह मोबाइल फोन का उत्पादन 18,000 करोड़ रुपये से 28 गुना बढ़कर 5.45 लाख करोड़ रुपये हो गया है। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता देश है। मोबाइल फोन निर्यात में 127 गुना वृद्धि सिद्ध करती है कि भारत अब आयात पर निर्भर नहीं, बल्कि वैश्विक जरूरतों को पूरा करने वाला निर्यातक बन चुका है।

कृषि और खाद्य उत्पादनरू हमारे किसान भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। सरकार का लक्ष्य किसानों को वैश्विक निर्यात बाजारों से जोड़ना है। 2013–14 में बागवानी उत्पादन 280.7 मिलियन टन था, जो अब 31 प्रतिशत बढ़कर 367.7 मिलियन टन हो गया है। मत्स्य उत्पादन में 104 प्रतिशत की अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज की गई है, जो 96 लाख टन से 195 लाख टन तक पहुंच गई है। कृषि–खाद्य निर्यात में प्रसंस्कृत भोजन की हिस्सेदारी 13.7 से बढ़कर 20.4 प्रतिशत हो गई है। प्रौद्योगिकी और नवाचाररू नया भारत नवाचार का भारत है। 2014 से पहले देश में बमुश्किल 350 स्टार्टअप थे, आज 2026 में भारत के पास 2.3 लाख से अधिक मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स की फौज है। यूनिकार्न कंपनियों की संख्या चार से बढ़कर 120 से अधिक हो गई है। अंतरिक्ष के क्षेत्र में स्टार्टअप्स एक से बढ़कर लगभग 440 हो गए हैं। भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 80वें स्थान से छलांग लगाकर 38वें स्थान पर आ गया है। एआइ, 6जी, क्वांटम प्रौद्योगिकी और डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर के जरिये देश के युवाओं को भविष्य के लिए तैयार किया जा रहा है।

गति शक्तिः पीएम गति शक्ति योजना के तहत भारत में मल्टीमाडल कनेक्टिविटी का जाल बिछाया जा रहा है। राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई 91,287 किमी से 60 प्रतिशत बढ़कर 1,46,000 किमी से अधिक हो गई है। हाई–स्पीड कारिडोर्स का निर्माण 32 गुना बढ़कर 3,052 किमी हो गया है। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला देश है। रेलवे का लगभग पूर्ण रूप से विद्युतीकरण किया जा चुका है, जो कभी केवल 20 प्रतिशत तक सीमित था। हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत परिवहन क्षेत्र में स्वच्छ ऊर्जा के युग का शंखनाद है। रक्षा शक्तिरू भारत रक्षा उपकरणों का आयातक नहीं, बल्कि निर्यातक बन रहा है। रक्षा उत्पादन में लगभग चार गुना की वृद्धि हुई है और रक्षा निर्यात 56 गुना बढ़कर 38,424 करोड़ रुपये के स्तर को छू चुका है। श्मिशन सुदर्शन चक्रश् और हाइपरसोनिक रक्षा प्रौद्योगिकियों ने हमारी सेना को अजेय बना दिया है। सशस्त्र माओवाद पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया गया है और देश के ताने–बाने को तोड़ने वाले वैचारिक (अर्बन) नक्सलियों से निपटने के लिए राष्ट्र पूरी तरह सतर्क है।

हरित और नीली अर्थव्यवस्थारू भारत आज जलवायु परिवर्तन के खिलाफ वैश्विक लड़ाई का नेतृत्व कर रहा है। हमारी नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 76.38 गीगावाट से बढ़कर 288.58 गीगावाट हो गई है। सौर ऊर्जा क्षमता में 59 गुना का भारी उछाल आया है। भारत अब स्थापित नवीकरणीय और सौर क्षमता में विश्व में तीसरे स्थान पर है। 2025 के ऐतिहासिक शांति अधिनियम ने परमाणु ऊर्जा के विस्तार का मार्ग प्रशस्त किया है। गैस ग्रिड का विस्तार 70 से 700 शहरों तक हो गया है। नीली अर्थव्यवस्था के तहत मत्स्य पालन 142 प्रतिशत बढ़ा है। इसके साथ ही इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री 1.5 लाख से बढ़कर 25 लाख हो गई है, जो स्वच्छ भारत के संकल्प को पुष्ट करता है। साफ्ट पावररू भारत के सांस्कृतिक मूल्य आज विश्व के लिए मार्गदर्शक बन रहे हैं। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की संख्या 31 से बढ़कर 44 हो गई है। श्अंतरराष्ट्रीय योग दिवसश आज पूरी दुनिया में मनाया जाता है। श्हील इन इंडियाश और आयुर्वेद ने भारत की स्वास्थ्य सेवाओं को वैश्विक मंच पर स्थापित किया है। विदेशी पर्यटकों की आवक में 43 प्रतिशत की शानदार वृद्धि दर्ज की गई है। वेव्स समिट जैसे आयोजनों ने भारत की रचनात्मक और एनिमेशनध्गेमिंग अर्थव्यवस्था को एक साफ्ट पावर के रूप में प्रस्तुत किया है।

हर मिनट का हिसाब दे संसद

प्रो. गौरव वल्लभ

पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च के संसदीय उत्पादकता डैशबोर्ड के अनुसार संसद के मानसून सत्र में लोकसभा ने 17.5 घंटे यानी निर्धारित समय का 15 प्रतिशत काम किया, जबकि राज्यसभा ने 37.37 घंटे यानी 33 प्रतिशत काम किया। पूरे सत्र में प्रत्येक सदन के लिए लगभग 114 घंटे निर्धारित थे। इस हिसाब से लोकसभा में करीब 96.5 घंटे और राज्यसभा में 76.6 घंटे का काम नहीं हो सका। दोनों सदनों को जोड़ें तो कुल 173.1 सदन–घंटे का काम नहीं हुआ। आम तौर पर बताए जाने वाले प्रति सदन प्रति मिनट 1.25 लाख रुपये को 173.1 घंटे की कमी पर लागू करें तो पूरे सत्र की संकेतात्मक अवसर लागत करीब 130 करोड़ रुपये बैठती है। यह ऐसी धनराशि नहीं है, जिसे वापस पाया जा सकता था। कर्मचारियों, सुरक्षा, प्रसारण और बुनियादी ढांचे पर खर्च चलता ही रहता है।

यह करदाताओं के पैसे से उपलब्ध उस क्षमता का पैमाना है, जो संसदीय काम में नहीं रूपांतरित हो सकी। वित्तीय लागत तो समस्या का केवल दिखाई देने वाला सिरा है। जब प्रश्नकाल नहीं चलता तो मंत्री उन सवालों से बच जाते हैं, जिन्हें पूछने के लिए करदाता संसद का खर्च उठाते हैं। जब शून्यकाल शोर में डूब जाता है तो निर्वाचन क्षेत्रों की चिंताओं का राष्ट्रीय मंच छिन जाता है। जब विधायी समय सिकुड़ता है तो विधेयक या तो अटकते हैं या पर्याप्त पड़ताल के बिना पारित हो जाते हैं। यह अब अपवाद नहीं, आदत बनती जा रही है। संसद तब काम करती है, जब राजनीतिक पक्ष तमाशे की जगह विचार–विमर्श को चुनते हैं। जेन–जी और मिलेनियल्स गतिविधि और उपलब्धि का फर्क अच्छी तरह समझते हैं। उनकी पेशेवर और नागरिक जिंदगी रियल–टाइम डैशबोर्ड, सेवा रेटिंग, डिलीवरी की समयसीमा और सामने दिखते परिणामों से जुड़ी है। वे पूछते हैं, 'आपकी मौजूदगी से बदला क्या?' सर्वोच्च विचार–विमर्श संस्था के लिए वे इस पुराने मानक को स्वीकार नहीं करेंगे।

संसद कोई कंपनी नहीं है और सांसद कार्यपालिका के कर्मचारी नहीं हैं। असहमति भी एक पक्ष है। एक तीखा सवाल काम है। किसी विधेयक के विरुद्ध तर्कपूर्ण भाषण काम है। विरोध भी संसद का वैध साधन है, लेकिन बार–बार नारेबाजी करके सदन स्थगित कराना अलग बात है। इससे एक समूह का विरोध हर दूसरे सदस्य और मतदाता के अधिकार पर वीटो बन जाता है। संसद को सुचारु रूप से चलाने की जिम्मेदारी साझा है। कामकाज की सूची पारदर्शी ढंग से रखना, पर्याप्त समय पहले सूचना देना, विपक्ष के जायज मुद्दों के लिए स्थान देना और मंत्रियों से जवाब सुनिश्चित करना सरकार का पहला दायित्व है, लेकिन संस्थागत कामकाज में विपक्ष कोई दर्शक नहीं है। जिस मंच से वह कार्यपालिका की जांच करता है, उसे बचाए रखने की उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी उसकी भी है। सदन चलाने की जिम्मेदारी एक दल को सौंपकर दूसरा दल व्यवधान को अपनी मुख्य उपलब्धि नहीं बना सकता। संसद में जिस मंत्री से जवाब मांगा जा रहा हो, वह हर आरोप सुनकर सदन में उत्तर देने को तैयार हो, तो संसदीय मंच से इन्कार क्यों? जवाब मांगना और फिर उसे सुनने से इन्कार करना जांच नहीं, विरोधाभास है। अमित शाह के मामले में ऐसा ही हुआ।

जो विपक्ष जवाबदेही की मांग करता है, उसका मूल्यांकन उसके सवालों, विकल्पों और हस्तक्षेपों की गुणवत्ता से होना चाहिए, न कि उसके कारण हुए स्थगनों की संख्या से। उपस्थिति और भत्ते की व्यवस्था इस प्रतीकात्मक समस्या को सामने लाती है। वर्तमान दैनिक भत्ता 2,500 रुपये है और संसद की बैठक वाले दिन सदस्य इस भत्ते की पात्रता प्रक्रिया के तहत उपस्थिति रजिस्टर पर हस्ताक्षर करता है। यात्रा भत्ता एक अलग वैधानिक अधिकार है और उसे इन हस्ताक्षरों से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। 2026–27 में लोकसभा और राज्यसभा के लिए 1,491.99 करोड़ रुपये के संयुक्त आवंटन के सामने यह राशि मामूली है, पर संदेश महत्वपूर्ण है। हस्ताक्षर मौजूदगी साबित करता है, कार्य–निष्पादन नहीं।

भारत को सरकार, विपक्ष और पीठासीन अधिकारियों की सहमति से एक 'संसदीय कार्य–निष्पादन संकल्प' चाहिए। इसका पहला नियम सरल होना चाहिएरू बिना भरपाई के कोई घंटा बर्बाद नहीं होगा। यदि व्यवधान के कारण निर्धारित काम नहीं हो पाता, तो सदन देर तक बैठे, एक अतिरिक्त दिन काम करे या उसी सत्र में उस समय की भरपाई करे। राजनीतिक असहमति कार्यसूची का क्रम बदल सकती है, लेकिन वह कुल संसदीय काम को कम नहीं कर सकती। दूसरा, विरोध के अधिकार के साथ बहस की सुनिश्चित राह भी होनी चाहिए। राजनीतिक दलों को यह संकल्प लेना चाहिए कि एक बार समय आवंटित होने पर बहस अवश्य होगी। सरकार जवाब दे, विपक्ष सुने, प्रतिवाद करे और मतदान करे। जवाबदेही संसद की दोतरफा प्रक्रिया है, टेलीविजन का एकतरफा प्रदर्शन नहीं। तीसरा, संसद को एक समान रियल–टाइम डैशबोर्ड प्रकाशित करना चाहिए।

इसमें सत्यापित उपस्थिति, सदन में मौजूद रहने की अवधि, पूछे गए प्रश्न, बहस में भागीदारी, समिति का काम, गैर–सरकारी सदस्यों का कार्य, जांच के लिए भेजे गए विधेयक, गंवाया गया समय और उसकी भरपाई का ब्योरा हो। संसद, विचार–विमर्श और समाधान के लिए है, ठहराव को तात्कालिक राजनीतिक लाभ में बदलने के लिए नहीं।

भारत के संचार नेटवर्क की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए संचार विभाग ने 14 स्वदेशी क्वांटम उत्पादों का अनावरण किया

क्वांटम उत्पादों की शृंखला क्वांटम युग में सुरक्षित और भविष्य के लिए तैयार संचार हेतु क्वांटम कुंजी वितरण और पोस्ट–क्वांटम क्रिप्टोग्राफी समाधान प्रदान करती है

नई दिल्ली। भारत सरकार के संचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग के प्रमुख दूरसंचार अनुसंधान एवं विकास केंद्र, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स (सी–डॉट) ने नई दिल्ली में अपने 43वें स्थापना दिवस समारोह के दौरान क्वांटम कुंजी वितरण (क्यू के डी) और पोस्ट–क्वांटम क्रिप्टोग्राफी (पी क्यू सी) के क्षेत्रों में विकसित 14 स्वदेशी क्वांटम उत्पादों का अनावरण किया।

अनावरण किए गए उत्पादों में शामिल हैं

क्यू–अक्षय सीडी: एक कॉम्पैक्ट, फाइबर–आधारित क्वांटम कुंजी वितरण (क्यू के डी) प्रणाली है जो 1यू आकार में एकतरफा (सीओडब्ल्यू) और विभेदक चरण शिफ्ट (डीपीएस) प्रोटोकॉल पर आधारित है। यह फाइबर नेटवर्क पर सुरक्षित क्वांटम कुंजी निर्माण और वितरण को सक्षम बनाती है।

क्यू–अक्षय एमडी: यह एक फाइबर–आधारित क्यूकेडी प्रणाली है जो मेजरमेंट डिवाइस इंडिपेंडेंट (एम डी आई) प्रोटोकॉल पर आधारित है और माप उपकरणों से जुड़ी कमियों के लिए बेहतर सुरक्षा प्रदान करती है। यह सुरक्षित क्वांटम कुंजी वितरण के लिए सी–डॉट का अगली पीढ़ी का दृष्टिकोण है।

सी–एसपीडी: एक सिंगल–फोटॉन डिटेक्टर, क्वांटम संचार प्रणालियों में उपयोग किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण उप–मॉड्यूल।

सी–आरडी: क्वांटम संचार प्रणालियों में उपयोग होने वाले तीव्रता और चरण मॉड्यूलेटरों को संचालित करने के लिए डिजाइन किया गया एक वाइडबैंड आरएफ ड्राइवर। यह उच्च–प्रदर्शन क्वांटम संचार अनुप्रयोगों को सक्षम करने के लिए एक महत्वपूर्ण उप–मॉड्यूल के रूप में कार्य करता है।

क्यू–सेतु: एक क्वांटम–सुरक्षित एन्क्रिप्टर है जिसे 80 एमबीपीएस तक की डेटा संचरण की दर के साथ लेयर 3 संचार को सुरक्षित करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह उभरते क्वांटम युग के खतरों से डेटा की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय मानक और प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईएसटी) के पोस्ट–क्वांटम क्रिप्टोग्राफी (पी क्यू सी) एल्गोरिदम को शामिल करता है।

क्यू– महासेतु: एक अगली पीढ़ी का, व्यावसायिक स्तर का क्वांटम–सुरक्षित एन्क्रिप्टर है जो 40 जी पी एस तक की डेटा संचरण की क्षमता वाले लेयर 2ध्3 नेटवर्क को सपोर्ट करता है। यह एंटरप्राइज और महत्वपूर्ण संचार नेटवर्क के लिए उच्च गति और क्वांटम–प्रतिरोधी सुरक्षा प्रदान करने के लिए एनआईएसटी पीक्यूसी एल्गोरिदम का उपयोग करता है।

क्यू–विक्रम: एक रक्षा–स्तरीय क्वांटम–सुरक्षित एन्क्रिप्टर जो लेयर 2ध्3 नेटवर्क के लिए 1जीबीपीएस तक का डेटा संचरण की दर प्रदान करता है। यह संवेदनशील और रणनीतिक संचार के लिए बेहतर सुरक्षा प्रदान करने हेतु एनआईएसटी पी क्यू सी एल्गोरिदम को समाहित करता है।

क्यू–अमोघ: एक उच्च–गति वाला क्वांटम–सुरक्षित ऑप्टिकल एन्क्रिप्टर जो लेयर 1 पर 200 जीबीपीएस तक का डेटा संचरण की दर प्रदान करता है। एनआईएसटी पीक्यूसी एल्गोरिदम पर आधारित, इसे उभरते क्वांटम खतरों से उच्च–क्षमता वाले ऑप्टिकल संचार लिंक को सुरक्षित करने के लिए डिजाइन किया गया है।

क्यू–दर्शन: एक क्वांटम–सुरक्षित वीडियो आईपी फोन, जो वॉइस और वीडियो संचार की सुरक्षा के लिए एनआईएसटी पीक्यूसी एल्गोरिदम का उपयोग करता है। यह आईपी–आधारित संचार प्रणालियों में सीधे क्वांटम–सुरक्षित सुरक्षा प्रदान करता है।

क्यू–वचन: एनआईएसटी पी क्यू सी एल्गोरिदम का उपयोग करने वाला एक क्वांटम–सुरक्षित इन–लाइन नोड, जो आईपी फोन के लिए बनाया गया है। यह मौजूदा आईपी फोन को क्वांटम सुरक्षा से लैस कर सकता है।

क्यू–रक्षक: एक क्वांटम–सुरक्षित एंटरप्राइज नेटवर्क समाधान है जिसे उद्यम संचार और नेटवर्क अवसंरचना की सुरक्षा के लिए डिजाइन किया गया है। यह वर्तमान और भविष्य के क्रिप्टोग्राफिक खतरों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए एनआईएसटी पी क्यू सी एल्गोरिदम को शामिल करता है।

क्यू–वायु: एक क्वांटम–सुरक्षित वायरलेस पॉइंट–टू–पॉइंट नेटवर्क समाधान है जिसे वायरलेस संचार लिंक को सुरक्षित करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह वायरलेस कनेक्टिविटी के लिए क्वांटम–प्रतिरोधी सुरक्षा प्रदान करने के लिए एनआईएसटी पी क्यू सी एल्गोरिदम का उपयोग करता है।

क्यू–वज्र1000: क्वांटम सुरक्षा के साथ मौजूदा संचार नेटवर्क को अपग्रेड करने के लिए डिजाइन किया गया एक क्वांटम–सुरक्षित एक्सेस नोड। यह जीपीओएन और वायरलेस रेडियो जैसी तकनीकों को सपोर्ट कर सकता है, जिससे क्वांटम–सुरक्षित सुरक्षा को मौजूदा नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर में एकीकृत किया जा सकता है।

क्यू–पराक्रम: एक रक्षा–स्तरीय क्वांटम–सुरक्षित एन्क्रिप्टर जो लेयर 2ध्3 नेटवर्क के लिए 1जीबीपीएस तक का डेटा संचरण की दर प्रदान करता है। इसमें एनआईएसटी पी क्यू सी एल्गोरिदम और अन्य मालिकाना एल्गोरिदम शामिल हैं और इसे रणनीतिक और रक्षा संचार के लिए मजबूत क्वांटम–प्रतिरोधी सुरक्षा प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है।

क्वांटम उत्पाद श्रृंखला क्वांटम–सुरक्षित एन्क्रिप्शन, सुरक्षित संचार और क्वांटम संचार प्रणालियों के लिए महत्वपूर्ण घटकों के समाधान प्रदान करती है, जो उद्यम, दूरसंचार, वायरलेस, ऑप्टिकल, रणनीतिक और रक्षा अनुप्रयोगों की आवश्यकताओं को पूरा करती है। क्वांटम उत्पाद श्रृंखला सुरक्षित क्वांटम कुंजी निर्माण और वितरण को सक्षम करने के लिए क्यूकेडी प्रौद्योगिकियों और प क्यू सी –आधारित समाधानों को जोड़ती है और भविष्य के क्वांटम कंप्यूटरों से उत्पन्न खतरों से संचार की सुरक्षा के लिए डिजाइन की गई है। सी–डॉट का क्वांटम पोर्टफोलियो विशेष क्वांटम संचार घटकों को भी शामिल करता है जिनका उपयोग इस क्षेत्र में कार्यरत पारिस्थितिकी तंत्र द्वारा मौजूदा और अगली पीढ़ी के नेटवर्क के लिए क्वांटम–सुरक्षित सुरक्षा समाधान बनाने में किया जा सकता है।

ये उत्पाद केंद्र सरकार के स्वदेशी अनुसंधान और नवाचार को भारत के संचार अवसंरचना को उभरते क्वांटम युग में सुरक्षित करने के लिए व्यावहारिक समाधानों में परिणत करने के लक्ष्य को दर्शाते हैं। इन उत्पादों को क्वांटम कंप्यूटिंग के आने से जुड़ी उभरती साइबर सुरक्षा चुनौतियों का समाधान करने और भारत के संचार नेटवर्क की सुरक्षा और मजबूती को बढ़ाने के लिए विकसित किया गया है।

गणमान्य व्यक्तियों द्वारा क्वांटम उत्पाद श्रृंखला पुस्तिका का भी विमोचन किया गया। जिसमें सी–डॉट के स्वदेशी क्वांटम समाधानों को संकलित किया गया है। पुस्तिका में सी–डॉट द्वारा क्वांटम केडी और पीक्यूसी के क्षेत्र में किए गए कार्यों को प्रस्तुत किया गया है और सुरक्षित, लचीली और भविष्य के लिए तैयार संचार प्रौद्योगिकियों के विकास की दिशा में किए गए प्रयासों पर प्रकाश डाला गया है। पुस्तिका तक पहुंचने के लिए इस लिंक का अनुसरण करें:

Created by Universal Document Converter

एनआईटी श्रीनगर इंडिया टुडे रैंकिंग 2026 में भारत के टाप टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ में 19वें स्थान पर पहुंचा

डायरेक्टर ने संस्थान की उत्कृष्टता के प्रति सामूहिक प्रतिबद्धता की सराहना की

जम्मू/श्रीनगर। नेशनल इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलाजी श्रीनगर ने इंडिया टुडे रैंकिंग 2026 में उल्लेखनीय सुधार दर्ज किया है। संस्थान ने भारत की टाप टेक्निकल यूनिवर्सिटीज में 19वां स्थान हासिल किया है जबकि 2025 में यह 22वें स्थान पर था। तीन स्थानों की यह बढ़त संस्थान की शैक्षणिक और संस्थागत उत्कृष्टता की दिशा में जारी यात्रा में एक और मील का पत्थर है। यह शिक्षा, रिसर्च, इनोवेशन और समग्र संस्थागत विकास में संस्थान की निरंतर प्रगति को दर्शाता है।

एनआईटी श्रीनगर प्रशासन ने इस उपलब्धि का स्वागत किया है। प्रशासन ने राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर रैंकिंग का श्रेय फैकल्टी, छात्रों, रिसर्चर्स, नान–टीचिंग स्टाफ, पूर्व छात्रों और अन्य हितधारकों के निरंतर और सामूहिक प्रयासों को दिया है। एनआईटी श्रीनगर के डायरेक्टर प्रो. अनुराग मिश्रा ने इस उपलब्धि पर पूरे संस्थान परिवार को बधाई दी। उन्होंने कहा कि बेहतर रैंकिंग उत्कृष्टता के प्रति संस्थान की सामूहिक प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

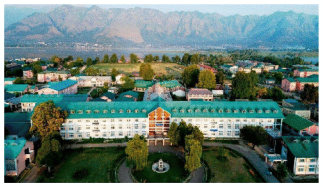

उन्होंने कहा कि एनआईटी श्रीनगर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, अत्याधुनिक रिसर्च, इनोवेशन और इंडस्ट्री–एकेडेमिया के बीच मजबूत सहयोग पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखेगा, साथ ही अपने शैक्षणिक इकोसिस्टम और राष्ट्रीय स्तर पर अपनी स्थिति को और मजबूत करेगा। रजिस्ट्रार प्रो. अतीकुर रहमान ने भी फैकल्टी, छात्रों, रिसर्चर्स और स्टाफ को बधाई दी। उन्होंने कहा कि बेहतर रैंकिंग संस्थान के शैक्षणिक और रिसर्च माहौल को मजबूत करने के लिए किए जा रहे निरंतर प्रयासों की पहचान है।

एनआईटी श्रीनगर में एनआईआरएफ के चेयरमैन प्रो. बाबर अहमद ने बेहतर रैंकिंग को संस्थान के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि 2026 में 22वें स्थान से 2026 में 19वें स्थान पर पहुचना एनआईटी श्रीनगर की निरंतर प्रगति और बढ़ती शैक्षणिक प्रतिष्ठा को दर्शाता है। एनआईआरएफ के नोडल आफिसर और एनआईटी श्रीनगर के फिजिक्स डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर डा. विजय कुमार ने कहा कि इंडिया टुडे रैंकिंग में सुधार, एकेडमिक एक्सीलेंस, क्वालिटी एजुकेशन, रिसर्च और इनोवेशन के लिए एनआईटी श्रीनगर की लगातार कोशिशों को दिखाता है। यह नई रैंकिंग एनआईटी श्रीनगर के लिए लगातार ऊपर की ओर बढ़ने का संकेत है। इंस्टीट्यूट भारत की टाप टेक्निकल यूनिवर्सिटीज में 2026 में 22वें स्थान से बेहतर होकर 2026 में 19वें स्थान पर पहुच गया है।

कम पानी दे रहा बोरवेल, गांवों में जलापूर्ति प्रभावित; जल जीवन मिशन की व्यवस्था पर उठे सवाल

घगवाल (निखिल पगोत्रा)। उप जिला घगवाल के नौनाथ गांव में राष्ट्रीय राजमार्ग–44 के किनारे स्थित ट्यूबवेल का बोरवेल कम मात्रा में पानी दे रहा है, जिसके चलते गांवों में लोगों के घरों तक पानी की पूरी सप्लाई नहीं पहुच पा रही है। जल जीवन मिशन के कर्मचारियों के अनुसार, बोरवेल से पर्याप्त पानी उपलब्ध नहीं होने के कारण जलापूर्ति प्रभावित हो रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस ट्यूबवेल को बने कई वर्ष बीत चुके हैं और अब इसकी स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। जिस प्रकार समय के साथ किसी पुरानी व्यवस्था की क्षमता कम होने लगती है, उसी तरह इस ट्यूबवेल की कार्यक्षमता भी प्रभावित होती दिखाई दे रही है। जल जीवन मिशन के कर्मचारियों का कहना है कि लोग जब उनसे पूछते हैं कि उनके घरों में पानी क्यों नहीं पहुच रहा, तो उनके पास भी इसका सीधा समाधान नहीं है। कर्मचारियों के मुताबिक, जब बोरवेल ही पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध नहीं कराएगा, तो लोगों के घरों तक नियमित और पर्याप्त पानी पहुच ना मुश्किल होगा। वहीं, पानी के भंडारण के लिए बनाए गए टैंक की हालत भी खराब बताई जा रही है। टैंक में कई जगहों से पानी रिसने की शिकायत सामने आ रही है, जिससे उपलब्ध पानी के संरक्षण को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि यदि समय रहते ट्यूबवेल और पानी के टैंक की मरम्मत एवं उचित व्यवस्था नहीं की गई तो आने वाले समय में क्षेत्र में पेयजल की समस्या और गंभीर हो सकती है। लोगों ने जल जीवन मिशन विभाग से मामले का संज्ञान लेकर बोरवेल की जांच, आवश्यक मरम्मत और पानी की नियमित सप्लाई सुनिश्चित करने की मांग की है।

यूजीसी कानून के खिलाफ बरवाल में सामान्य वर्ग के लोगों का रोष, कानून वापस लेने की मांग

कठुआ, 31 अगस्त। कठुआ के गांव बरवाल में सामान्य वर्ग के लोगों और बुजुर्गों ने यूजीसी से संबंधित कानून के खिलाफ रोष प्रकट करते हुए केंद्र सरकार से इसे वापस लेने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि कानून में सामान्य वर्ग के बच्चों के हितों और सुरक्षा का पर्याप्त ध्यान नहीं रखा गया है।

उन्होंने कहा कि किसी भी बच्चे को उसके जन्म या वर्ग के आधार पर अपराधी की नजर से नहीं देखा जाना चाहिए। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से मांग की कि सभी वर्गों के बच्चों के अधिकारों और सुरक्षा को समान रूप से सुनिश्चित किया जाए तथा संबंधित कानून की समीक्षा कर सामान्य वर्ग के बच्चों के हितों की रक्षा की जाए। इस दौरान उपस्थित लोगों ने केंद्र सरकार से मामले पर गंभीरता से विचार करते हुए कानून को वापस लेने की मांग उठाई।

जेहानपोरा में खुदाई से कश्मीर की विरासत के बारे में समझ बढ़ेगी: रमन सूरी

जम्मू। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रमन सूरी ने बारामूला के जेहानपोरा में चल रही पुरातत्व खुदाई को एक अहम कोशिश बताया है। इससे कश्मीर की प्राचीन विरासत और भारतीय उपमहाद्वीप व मध्य एशिया के साथ इसके ऐतिहासिक संबंधों के बारे में समझ काफी गहरी हो सकती है।

उन्होंने जम्मू–कश्मीर के अभिलेखागार, पुरातत्व और संग्रहालय विभाग की कोशिशों का स्वागत किया, जो कश्मीर विश्वविद्यालय के सेंटर फार सेंट्रल एशियन स्टडीज के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू–कश्मीर में ऐतिहासिक रूप से अहम दूसरी जगहों पर भी ऐसी वैज्ञानिक खुदाई को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। सूरी ने जेहानपोरा से मिली चीजों के सही दस्तावेजीकरण, संरक्षण और लोगों के सामने पेश करने की भी मांग की ताकि ये खोजें आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रहें और आगे चलकर इस इलाके की सांस्कृतिक और पर्यटन पहचान का हिस्सा बन सकें।

हमें पुरातत्व को सबूतों के जरिए अपनी बात कहने देनी चाहिए। जेहानपोरा में दबे अवशेष हमें कश्मीर के इतिहास के ऐसे अध्याय बता सकते हैं जो लगभग दो हजार सालों से गायब हैं। सूरी ने कहा कि मिली हर कलाकृति, पहचानी गई हर संरचना और तय की गई हर वैज्ञानिक तारीख उस ऐतिहासिक पहेली में एक और टुकड़ा जोड़ेगी।

सूरी ने कहा कि यह खुदाई बहुत अहम है क्योंकि माना जाता है कि इस जगह पर लगभग 2,000 साल पुरानी बस्ती के अवशेष हैं। खुदाई का दूसरा चरण लगभग 10 एकड़ इलाके में किया जा रहा है और इसके लगभग 100 दिनों तक चलने की उम्मीद है। इससे ऐसी संरचनाएं, कलाकृतियां और दूसरी भौतिक चीजें सामने आ सकती हैं जो इतिहासकारों को कश्मीर के अतीत के एक अहम लेकिन कम खोजे गए अध्याय को फिर से समझने में मदद कर सकती हैं।

उन्होंने कहा कि शुरुआती खोजों ने पहले ही काफी दिलचस्पी पैदा कर दी है। खबरों के मुताबिक पुरातत्वविदों को प्राचीन संरचनाओं के अवशेष, मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े, तांबे की चीजें और दूसरी पुरातात्विक सामग्री मिली है। ये खोजें बताती हैं कि जेहानपोरा में मौजूद टीले सिर्फ प्राकृतिक बनावट नहीं है बल्कि ये एक बहुत बड़े प्राचीन बौद्ध परिसर के अवशेष हो सकते हैं।

जेहानपोरा में मिट्टी की हर परत में एक ऐसी कहानी बताने की क्षमता है जो सदियों से दबी हुई है। यह खुदाई सिर्फ पुरानी संरचनाओं को खोजने के बारे में नहीं है। सूरी ने कहा कि इसका मकसद ऐसे सबूत जुटाना है जिनसे प्राचीन कश्मीर के इतिहास, संस्कृति, अर्थव्यवस्था, शिक्षा और बाहरी संपर्कों को फिर से समझा जा सके।

उन्होंने बताया कि वैज्ञानिक जांच जिसमें कार्बन डेटिंग और पुरातत्व की दूसरी आधुनिक तकनीकें शामिल हैं, से अवशेषों की उम्र का ज्यादा सटीक पता लगाने में मदद मिल सकती है। इस जगह से मिली चीजों से उस समय का पता चल सकता है जब यह बस्ती फली–फूली थी, यहां मौजूद बौद्ध संस्थानों की प्रकृति, वास्तुकला की परंपराओं, मिट्टी के बर्तनों और तकनीकी तौर–तरीकों और दूसरे इलाकों के साथ कश्मीर के सांस्कृतिक और व्यापारिक संबंधों के बारे में जानकारी मिल सकती है।

सूरी ने कहा कि यह संभावना बहुत अहम है कि जेहानपोरा बस्ती से उस प्राचीन बौद्ध नेटवर्क में कश्मीर की भूमिका पर रोशनी पड़ सकती है जो इस इलाके को गंधार, मध्य एशिया और उपमहाद्वीप के दूसरे हिस्सों से जोड़ता था। उन्होंने कहा कि इसलिए इस खुदाई को सिर्फ एक पुरातत्व परियोजना के तौर पर नहीं बल्कि सबूतों पर आधारित इतिहास लिखने की कोशिश के तौर पर देखा जाना चाहिए।

Printer, Publisher, Owner, Editor by: Sanktha Prasad Singh Published from: GH Road Skara, Near Ladakh Public School, Leh (Ladakh) - 194104, Published from: Ladakh Imperial Printing press, Gh Skara, Near Ladakh Public School, Leh Ladakh, 194104, Mob.: Mob.: 9818069272, 8287390112, Email: ladakhtoday@gmail.com
**All disputes are subject to the exclusive jurisdiction of competent courts and forums in Leh - city.

Created by Universal Document Converter